छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 06 ■ अम्बिकापुर, मंगलवार 23 दिसम्बर 2025 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

धान का पुनर्चक्रण उजागर, शिवम फूड प्रोडक्ट में 3946 क्विंटल धान कम मिला

जिले में अवैध धान की खरीदी पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया हैं कलेक्टर ने

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। नवपदस्थ कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले में अवैध धान की खरीदी रोकने और धान के पुनर्चक्रण पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में खाद्य अधिकारी एवं जिला विपणन अधिकारी सरगुजा द्वारा संयुक्त रूप से 18 दिसंबर को मेसर्स शिवम फूड प्रोडक्ट, कंठी स्थित राइस मिल का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान धान के पुनर्चक्रण (री-साइक्लिंग) की पुष्टि हुई है।

निरीक्षण के समय राइस मिल संचालक निकित अग्रवाल उपस्थित पाए गए। मिल परिसर में ट्रक क्रमांक सीजी 15 डीएफ 5844 में हरे रंग के प्लास्टिक बोरी में 170 बोरी धान लोड किया जाना पाया गया। उक्त धान को मौके पर ही जप्त कर राइस मिल संचालक की सुपुर्दगी में दिया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि जूट बारदाने से धान को पलटी कर प्लास्टिक बोरी में भरकर धान खरीदी में खपाने के उद्देश्य से लोड किया जा रहा था। भौतिक सत्यापन के दौरान मिल परिसर में 17,933 बोरी धान, समिति

से लाए गए 1,900 बोरी धान से भरे तीन ट्रक तथा 6,553 बोरी पुराना चावल पाया गया। इस प्रकार कुल 19,833 बोरी धान, वजन 7,933.20 क्विंटल, मौके पर मौजूद मिला। दस्तावेजों के अनुसार एफसीआई अनुबंध अंतर्गत 9,120 क्विंटल का डीओ जारी हुआ था, जिसमें से 9,040 क्विंटल का उठाव हो चुका है। वहीं नान अनुबंध अंतर्गत 3,040 क्विंटल का डीओ जारी हुआ, जिसमें 2,740 क्विंटल का उठाव किया गया। इस प्रकार राइस मिल द्वारा कुल 11,880 क्विंटल (29,700 बोरी) धान का उठाव किया गया, जबकि भौतिक सत्यापन में 9,867 बोरी (3,946.80 क्विंटल) धान कम पाया गया।

अधिकारियों के अनुसार जांच में यह स्पष्ट होता है कि राइस मिल संचालक द्वारा कम पाए गए धान का उपयोग पुनर्चक्रण कर धान खरीदी में खपाने के लिए किया गया। निरीक्षण के समय मिलिंग कार्य एवं मशीन बंद पाई गई तथा स्टॉक संबंधी अभिलेख एवं दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जांच में यह कृत्य छत्तीसगढ़ चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 4(3), 4(5), 6(1) एवं 6(3) का उल्लंघन पाया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। मामले में आवश्यक कार्रवाई हेतु कलेक्टर को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रकरण में पंचनामा, कथन, जप्ती पत्रक एवं सुपुर्दगी पत्रक संलग्न किए गए हैं, जिस पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

अवैध धान संग्रहण पर जिला प्रशासन की सख्ती, 486 क्विंटल धान जप्त

नवपदस्थ कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशन में जिले में अवैध धान संग्रहण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने तथा कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से सघन जांच और कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को राजस्व विभाग, खाद्य विभाग एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने अंबिकापुर शहर में कार्रवाई करते हुए महामाया ट्रेडिंग, भगवती ट्रेडिंग एवं श्री श्याम ट्रेडिंग के परिसरों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान इन तीनों प्रतिष्ठानों में बड़ी मात्रा में धान का भंडारण पाया गया, जिसके संबंध में संबंधित व्यापारियों द्वारा वैध अनुमति अथवा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। दस्तावेजों के अभाव में टीम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल 486 क्विंटल अवैध धान जप्त किया गया। जप्त किए गए धान को सुरक्षित रूप से अभिरक्षा में लेकर आगे की वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। जिले में धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से संचालित है और किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, इसके लिए अवैध संग्रहण, जमाखोरी एवं अनियमित व्यापार पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संयुक्त टीमों द्वारा निरंतर निरीक्षण कर ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर अजीत वसंत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिले में अवैध रूप से धान का संग्रहण, परिवहन या नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि वे शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए वैध दस्तावेजों के साथ ही धान का क्रय-विक्रय करें।

दबंग की दादागिरी से बसकेपी में एक साल से सड़क निर्माण ठप

कोरवा जनजाति आज भी पक्की सड़क से वंचित

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। जिले में जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार भले ही प्रधानमंत्री जनमन योजना के जरिए सड़क, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी सच्चाई इन दावों की पोल खोल रही है। बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बसकेपी में पीएम जनमन योजना के तहत प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य बीते एक वर्ष से ठप पड़ा है। इयकी वजह एक दबंग व्यक्ति की खुली दादागिरी और प्रशासनिक सुस्ती है, जबकि यह सड़क विशेष पिछड़ी कोरवा जनजाति के लिए जीवनरेखा साबित हो सकती थी।

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि एक दबंग ने निजी भूमि होने का हवाला देकर निर्माण कार्य को जबरन रुकवा दिया। नतीजा यह है कि योजना कागजों में सिमट गई, कोरवा समाज आज भी कीचड़, बदहाली और दुश्वारियों में जीने को मजबूर है। बरसात के दिनों में हालात और भयावह हो जाता है। बीमारों को अस्पताल पहुंचाना चुनौती बन जाता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और दैनिक आवाजाही जोखिम भरी हो जाती है। यह केवल सड़क का मामला नहीं, बल्कि जनजातीय अधिकारों और विकास के साथ खुलेआम खिलवाड़ है। ग्रामीणों और ग्राम पंचायत बसकेपी के सरपंच ने सड़क निर्माण तत्काल शुरू कराने की मांग उठाई है। इस मुद्दे को लेकर समाज के लोगों ने छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के शासन-प्रशासन पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर अधूरे कार्य को चालू करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या जनजातीय विकास की योजनाएं दबंगों की दादागिरी की भेंट चढ़ती रहेंगी, या प्रशासन ठोस कार्रवाई कर पीएम जनमन योजना को जमीन पर उतारेगा।

आवेदन देने के बाद भी सीमांकन नहीं

ग्राम पंचायत बसकेपी के सरपंच नन्हे लाल लकड़ा ने कहा कि सड़क निर्माण को गांव के ही एक गुप्ता परिवार ने रोका है, इनका कहना है कि यह उनके स्वामित्व की सेटलमेंट जमीन है। उन्होंने तहसीलदार चांदो को जमीन का सीमांकन करने के लिए 17 नवंबर को आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक सीमांकन नहीं हुआ है।

स्वार्थ के लिए रोका सड़क निर्माण

गांव के विकास कुमार गुप्ता का कहना है कि एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कारण सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया है, जिससे विशेष पिछड़ी जनजातीय समाज को किसी प्रकार का लाभ न मिले। इससे जनजाति समाज के कई विकास कार्य अवरूद्ध हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने की स्थिति बन रही है। बरसात के दिनों में यह मार्ग काफी खराब हो जाता है, जिससे आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

पीटर खेस को मिली पीएचडी की उपाधि

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर के नवापारा स्थित सेंट जॉन्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्यरत पीटर खेस को डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। उनका यह शोध कार्य अमेरिकन कल्चर एट द क्रॉस रोड विषय पर केंद्रित था। पीटर ने अपना शोध कार्य बिलासपुर स्थित सीवी रमन विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन में पूरा किया। प्राचार्य को मिली इस उपाधि पर अधीनस्थ कर्मचारी व विद्यार्थियों ने खुशी जाहिर करते हुए उनका सम्मान किया।

केक कटवाने के लिए नहीं पहुंचने पर पड़ोसी से मारपीट

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। केक काटने के लिए बुलाने पर जब दंपती नहीं गए तो युवक नाराजगी जाहिर करते हुए केक को फेंक दिया और गाली-गलौज करते हुए पड़ोसी से मारपीट की घटना को अंजाम दिया।

जानकारी के मुताबिक केनाबांध में किराए के मकान में रहने वाला आकाश कुमार देवांगन, बाबरा मोटर्स में मिस्त्री का काम करता है। 18 दिसम्बर को वह काम करने के लिए गया था और शाम को घर आने के बाद खाना खा रहा था। रात्रि करीब 10.30 बजे पड़ोस में रहने वाले मुकेश सोनी ने आकाश और उसकी पत्नि को केक काटने के लिए घर के सामने मैदान में बुलाया। खाना खा रहे आकाश ने आने से मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर मुकेश सोनी केक को फेंक दिया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। गाली-गलौज सुनकर जब आकाश घर से बाहर निकला तो वह मारपीट करने लगा। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।

सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2024 में 1256, वर्ष 2025 में 1197 की मौत

आईजी ने संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में दोषमुक्ति के 709 प्रकरणों पर किया गहन विमर्श

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा ने हरितिमा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस राजपुर में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में सरगुजा संभाग के सभी जिले के पुलिस अधिकारी एवं न्यायालयों में कार्यरत लोक अभियोजन अधिकारी शामिल हुए। समीक्षा बैठक में सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों में दोषमुक्ति के कुल 709 प्रकरणों पर गहन चर्चा की गई। यातायात व्यवस्था की जिलेवार समीक्षा के दौरान सामने आया कि वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं के कुल 2016 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें मृतकों की संख्या 1256 थी, इसकी तुलना में वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटनाओं के कुल 1993 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें मृतकों की संख्या कुल 1197 है। पिछले वर्ष की तुलना में रेंज में सड़क दुर्घटनाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में कमी आई है, फिर भी सभी आम लोगों को यातायात नियमों का अक्षरश: पालन करने एवं दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करने हेतु लोगों को जागरूक करने निर्देशित किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक ने रेंज स्तरीय सेशन कोर्ट के 128 एवं लोवर कोर्ट के 581, कुल 709 दोषमुक्ति प्रकरणों की समीक्षा दौरान विशेष रूप से उन प्रकरणों पर चर्चा कर गंभीरता से कार्रवाई करने कहा, जिसमें न्यायालय में अग्रिम जमानत निरस्त होने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके

अलावा लंबित दोषमुक्ति प्रकरणों के विवेचना में विवेचकों के त्रुटि को सुधार हेतु पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा यदि नवीन कानून के तहत किसी प्रकरण के विवेचना में कोई परेशानी हो रही है तो अपने जिले के अभियोजन अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उन प्रकरणों का निकाल करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त कई प्रकरणों में ट्रायल के दौरान शिकायत झूठी पाई जाती है, जिसमें निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की कोशिश की जाती है, ऐसे में संबंधितों के विरुद्ध अभियोजन अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करने कहा गया ताकि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रुके। पुलिस महानिरीक्षक ने एक वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरण की प्रकरणवार समीक्षा कर संबंधित पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि अपने इकाई में राजपत्रित अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करते हुए तथा स्वयं के पर्यवेक्षण में लंबित प्रकरणों का यथाशीघ्र निकाल करें। नवीन कानून के तहत पंजीबद्ध प्रकरणों का पर्यवेक्षण कर कोर्ट, चिकित्सा जैसे अन्य प्रमुख विभागों से समन्वय स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए पेंडिंग प्रकरणों का निकाल करने कहा गया। रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर प्रशांत ठाकुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक एमसीबी रत्ना सिंह, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर वैभव बैंकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया पंकज पटेल एवं डॉ. ध्रुवेश जायसवाल, एसडीओपी पत्थलगांव जिला जशपुर सहित रेंज के लोक अभियोजन अधिकारी, रक्षित निरीक्षक बलरामपुर विमलेश कुमार देवांगन एवं आईजी कार्यालय के स्टेनो, रीडर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

इनके विरूद्ध करें एंड टू एंड कार्रवाई

एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में जिलों के राजपत्रित अधिकारियों को लीड करते हुए स्वयं सर्च कार्रवाई कराने तथा एनडीपीएस की धाराओं का प्रयोग करते हुए संपत्ति कुर्की, जप्ती की कार्रवाई करने, फाइनेंशियल एवं एंड तो एंड इन्वेस्टिगेशन कर अंतर राज्य गैंग तथा कोरियर कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा बाहरी राज्यों से आ रही प्रतिबंधित दवाओं के सप्लाई चैन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने व अपराधियों के विरुद्ध एनडीपीएस की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ इन एंड टू एंड तक कार्रवाई करके जप्त वाहनों को राजसात करने इकाई प्रमुखों को निर्देशित किया। उन्होंने जिलों में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने आदतन अपराधी, गुंडा बदमाशों का रिकॉर्ड तैयार कर पैनी नजर बनाए रखने कहा। जिलों में आ-सूचना संकलन को और मजबूत करने संदेहियों पर सख्त कार्यवाही, देर रात तक थाना क्षेत्र में चलने वाले होटल, ढाबा, दुकानों को समय पर बंद कराने तथा अड्डाबाजी वाले स्थान पर गस्त पेट्रोलिंग कराते हुए निगरानी बनाए रखने कहा।

105 साइबर अपराधों की समीक्षा

पुलिस महानिरीक्षक ने सरगुजा के 58, सूरजपुर के 9, जशपुर के 9 बलरामपुर के 4, कोरिया के 8, एमसीबी के 17, कुल 105 साइबर अपराधों की समीक्षा कर लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने कहा है। इसी प्रकार म्यूल एकाउंट, पीओएस एवं ऑनलाइन शिकायतों का निराकरण के संबंध में जिलावार विस्तृत समीक्षा कर म्यूल एकाउंट धारकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एक माह से अधिक समय से लंबित प्राथमिक जांच एवं 6 माह से अधिक समय से लंबित विभागीय जांच की जिलेवार समीक्षा करके लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने सभी पुलिस अधीक्षक को नियमित किया गया है।

पीलिया से पीड़ित अपने गर्दन पर चाकू से हमला किया, मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। पीलिया की बीमारी से पीड़ित अधेड़ अपने गर्दन पर चाकू से वार कर दिया, मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाते तक उसकी मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र निवासी अब्बू चंद यादव पिता मेघनाथ यादव 50 वर्ष अविवाहित था, जो पिछले दो साल से पत्थलगांव के बदियाखांड़ में अपनी बहन रीना यादव के यहां रहता था। एक सप्ताह से वह पीलिया से पीड़ित था और गांव में ही झाड़फूंक करा रहा था। 21 दिसम्बर को रात करीब 8-9 बजे के बीच खाना खाने के लिए बहन उसको उठाने गई तो कमरा अंदर से बंद था। आवाज लगाने पर भी दरवाजा नहीं खुला और न ही कोई प्रत्युत्तर सुनने को मिला। दीवाल के छेद से देखने पर भी कुछ नजर नहीं आया। दीवार को तोड़कर स्वजन अंदर गए तो अब्बू चंद लहूलुहान हाल में पड़ा था, उसके गर्दन से रक्तस्राव हो रहा था। स्वजन निजी वाहन से उसे पत्थलगांव स्वास्थ्य केन्द्र ले गए, यहां से प्राथमिक चिकित्सा के बाद रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे थे। यहां आपातकालीन चिकित्सा परिसर में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

एनएच के अधिकारियों और ठेकेदार के विरूद्ध अपराध दर्ज करने की मांग

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। राष्ट्रीय राजमार्ग में निम्न स्तरीय निर्माण करके किए जा रहे भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए समाजसेवियों ने कोतवाली थाना पुलिस को आवेदन प्रस्तुत किया है। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अंबिकापुर शहर क्षेत्र से गुजरी एनएच की खस्ताहाल हो चुकी सड़क में पैबंद लगाने का काम किया जा रहा है। उक्त सड़क निर्माण कार्य में मानक अनुरुप सामग्री का उपयोग नहीं करके अत्यंत निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। सड़क की मजबूती के लिए इमल्सन का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, जिससे सड़क तुरंत उखड़ रही है और दरार, गड्ढे की तस्वीर सामने आ रही है। घटिया निर्माण कार्य से आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग में व्यवसाय करने वाले और रहने वाले लोगों का कहना है कि काफी दिनों की प्रतीक्षा के बाद रोड बनना चालू हुआ, तो पेंच रिपेयरिंग करना सामने आया, इसमें भी गुणवत्ता को ताक पर रखा जा रहा है। इनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी किसी प्रकार का सुधार कार्य नहीं किया गया। इससे संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की बातें हो रही है। सामाजिक कार्यकर्ता राजेन्द्र बहादुर सिंह और अंकुर सिन्हा ने इसे संज्ञान में लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदार के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है, ताकि शासकीय धन की बर्बादी करने वालों को सबक मिल सके।

विद्युत ट्रांसफार्मर को गिराकर तेल, क्वाइल सहित अन्य सामानों की चोरी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। महामाया मंदिर के आसपास बिजली सप्लाई के लिए स्थित बिजली विभाग के कार्यालय सहायक यंत्री जोन-1 से अज्ञात चोर ट्रांसफार्मर को खम्भे से नीचे गिराकर तेल, क्वाइल, एचटी बुशिंग एवं एलटी बुशिंग चोरी करके ले गए। चोरी की इस वारदात से विभाग को 50 हजार रुपये से अधिक की क्षति पहुंची है। छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सहायक यंत्री, जोन क्रमांक-1 कैलाश देवांगन ने पुलिस अधीक्षक सरगुजा, कोतवाली थाना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए लिखित कार्यालयीन शिकायत पत्र में बताया है कि जोन अंतर्गत सक्रिय चोर गिरोह के द्वारा ट्रांसफार्मरों को खम्भे से जमीन में गिराकर उसके अंदर का क्वाइल, तेल, एलटी एवं एचटी बुशिंग चोरी किया जा रहा है। चोरों के द्वारा राजपूत होटल चौक में लगे 25 केव्ही के ट्रांसफार्मरए, दरिमा चौक में लगे पीपी इंडस्ट्रीज के 25 केव्ही क्षमता के ट्रांसफार्मर, महामाया ग्राउंड में लगे 16 केव्ही व 25 केव्ही के दो ट्रांसफार्मर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरी की घटना से विभाग को 50 हजार रुपये की आर्थिक क्षति पहुंची है। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 303(2) व छत्तीसगढ़ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136(1) (क) का मामला दर्ज किया है।

12 हजार क्विंटल से अधिक अवैध धान जब्त, 66 वाहन किए गए सीज

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा के निर्देशन में जिले में अवैध धान भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

अंतरराज्यीय सीमाओं पर 24 घंटे कड़ी निगरानी

प्रशासन द्वारा सभी अंतरराज्यीय सीमाओं एवं चेक पोस्टों पर चौकसी को और मजबूत करते हुए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके अंतर्गत संदिग्ध वाहनों एवं परिवहन गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

अब तक 102 प्रकरण दर्ज

पारदर्शी एवं निष्पक्ष धान खरीदी नीति के तहत अब तक जिले में कुल 102 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन प्रकरणों में 12,139.42 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। साथ ही 56 चार पहिया एवं 10 दोपहिया कुल 66 वाहनों को भी जब्त किया गया है, जो कि प्रशासन की सतत निगरानी और संयुक्त दलों की सक्रियता का परिणाम है।

आंतरिक चेक पोस्टों पर भी टीमों की तैनाती

कलेक्टर श्री कटारा के मार्गदर्शन में जिले के सभी अंतरराज्यीय एवं आंतरिक चेक पोस्टों पर विशेष टीमों को तैनात किया गया है। प्रत्येक अनुविभाग में गठित निगरानी दलों द्वारा रात्रिकालीन गश्त के साथ-साथ आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है तथा मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों एवं किसानों से अपील की है कि यदि उन्हें अवैध धान भंडारण या परिवहन से संबंधित कोई भी संदिग्ध गतिविधि अथवा सूचना प्राप्त हो, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

अवैध धान परिवहन पर संयुक्त टीम की कार्रवाई, 450 बोरी अवैध धान जब्त

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। धान खरीदी के सीजन में बिचौलियों द्वारा पड़ोसी राज्यों से अवैध धान खपाने की कोशिशों पर जिला प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रही है। प्रशासन की इसी सतर्कता के कारण विकासखंड रामचंद्रपुर एवं वाड्रफनगर अंतर्गत कुल 450 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। प्रशासन की मुस्तैदी से रामचन्द्रपुर अंतर्गत त्रिशूली हल्दी मोड़ में एक ट्रैक्टर वाहन की जांच के दौरान लगभग 100 बोरी अवैध धान पाया गया। संयुक्त टीम ने तत्काल मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए धान और वाहन को जब्त किया। इसी प्रकार विकासखण्ड वाड्रफनगर के धनवार चेक पोस्ट पर जांच के दौरान एक ट्रक में 350 बोरी अवैध धान पाया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए जब्त किया गया।

शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत मकरो के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बलरामपुर ने जानकारी दी है कि विकासखण्ड बलरामपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मकरो में शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत मकरो (खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित ग्राम रामनगर कला) का आबंटन निरस्त किया गया है। अब शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत मकरो का संचालन नवीन संचालन एजेंसी को प्रदान किया जाना है। इसके लिए इच्छुक संस्था संचालन करना चाहते हैं, वे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बलरामपुर में निर्धारित प्रारूप में 31 दिसम्बर 2025 कार्यालयीन समय तक आवेदन जमा कर सकते हैं। समय-सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठकआज

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। संयुक्त जिला कार्यालजय के सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 23 दिसम्बर को समय-सीमा की बैठक पश्चात आहूत की गई है। कलेक्टर श्री कटारा ने बैठक में संबंधित सदस्यों एवं विभागों के अधिकारियों को समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

कसलगिरि के पास पकड़ा गया 52 बोरी अवैध धान से भरा पिकअप

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। जिले में धान खरीदी को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशन में प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। एक ओर जहां खरीदी केंद्रों पर किसानों से निर्धारित दर पर धान की निर्बाध खरीदी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अवैध धान परिवहन, भंडारण और कालाबाजारी पर करारी चोट की जा रही है। इसी कड़ी में प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए गत दिनों ग्राम पंचायत कसलगिरि के पास अवैध रूप से धान का परिवहन करते हुए एक पिकअप वाहन को धर दबोचा। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची टीम ने

जब पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 15 ए 4002 की जांच की, तो उसमें 52 बोरियां अवैध धान लदी हुई पाई गईं। वाहन चालक से वैध दस्तावेजों की मांग की गई, लेकिन वह धान से संबंधित कोई भी अधिकृत कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रशासनिक अमले ने धान से भरे वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया। जब्त किए गए धान और वाहन को विधिवत सुपुर्दगी में लेकर लटोरी पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के बाद अवैध धान कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति है। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी, अवैध परिवहन या भंडारण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अंतर्गत आउट ऑफ स्टेट एक्सपोजर विजिट

प्रशासन की पहल से प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यार्थियों को मिला शैक्षणिक भ्रमण का अवसर

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में गणित और विज्ञान के प्रति जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग ने एक 'आउट ऑफ स्टेट एक्सपोजर विजिट' का आयोजन किया है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर में शैक्षणिक भ्रमण करने का अवसर मिला है। क्षेत्रीय भ्रमण में प्रारंभिक स्तर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय रामानुजगंज के 02 छात्र, कुसमी के 02 एवं राजपुर के 02 छात्र, इसी प्रकार माध्यमिक स्तर पर शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय बरतीकला के 02 छात्र एवं शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय दलधोवा के 02 छात्र, कुल 10 छात्र सहित 02 शिक्षक रवाना हुए।

इस शैक्षणिक भ्रमण में चयनित विद्यार्थी एवं शिक्षक दल 'क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर (उड़ीसा)' के लिए रवाना हुए। अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल, जिला शिक्षा अधिकारी श्री एम.आर. यादव, डीएमसी श्री चंद्र भूषण प्रसाद

गुप्ता एवं एडीपीओ श्री ओ.पी. गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर टीम को रवाना किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

इस भ्रमण से विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक एवं नवाचारपूर्ण शिक्षा का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा, जिससे वैज्ञानिक सोच, तार्किक क्षमता एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में विद्यार्थी विभिन्न मॉडल, प्रयोग, प्रदर्शनी और तकनीकी नवाचार देख सकेंगे, जो उनके शैक्षणिक विकास में सहायक होगी।

पारदर्शी व्यवस्था से बढ़ा किसानों का भरोसा

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले के धान उपार्जन केन्द्रों में तेजी से धान खरीदी कार्य किया जा रहा है। शासन के द्वारा किसानों के वास्तविक उपज को समर्थन मूल्य में खरीदी किए जाने से किसानों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं।

कुसमी विकासखंड के धान उपार्जन केन्द्र चांदो में धान विक्रय करने पहुंचे ग्राम बसकेपी के किसान श्री अखिलेश कुमार गुप्ता ने बताया कि वे 500 बोरी धान बिक्री करने आए हैं। उनके पास 12 एकड़ खेती जमीन है, जिसमें उन्होंने धान की उपज लिया है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने से किसानों को उपज का वास्तविक मूल्य मिल रहा है तथा धान विक्रय की राशि भी शीघ्र उनके बैंक खाते में जमा हो रही है। श्री गुप्ता ने बताया कि पिछले वर्ष धान बिक्री से प्राप्त राशि से उन्होंने घर की आवश्यकताओं को पूरा किया था और इस वर्ष भी वे घर की जरूरतों को पूरा करने के साथ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने और उनके भविष्य के लिए बचत करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय पर भुगतान होने से खेती-किसानी के कार्यों को सुचारू रूप से करने में सुविधा हो रही है और किसान अपनी आय का उपयोग कृषि विस्तार के लिए भी कर पा रहे हैं। उपार्जन केन्द्र की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि केन्द्र में पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता है तथा इलेक्ट्रॉनिक तौलाई के माध्यम से पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। किसानों से बिना विलंब के धान खरीदी की जा रही है। बेहतर व्यवस्था और किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

महतारी वंदन योजना बनी ग्रामीण महिलाओं के लिए संबल

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दिशा में शासन द्वारा शुरू की गई महतारी वंदन योजना आज ग्रामीण अंचलों की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। जिले की महिलाएं भी योजना से लाभान्वित होकर स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हो रही है। जिले के विकासखण्ड वाड्रफनगर के ग्राम रघुनाथनगर की निवासी श्रीमती ओमलता एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। सीमित आय, बढ़ती महंगाई और घरेलू ज़िम्मेदारियों के बीच उनका जीवन संघर्षों से भरा था। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी कई बार कठिन हो जाता था। लेकिन ओमलता के जीवन में बदलाव तब आया, जब उन्हें मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन हेतु शुरू

की गई महतारी वंदन योजना की जानकारी मिली। योजना के बारे में जानकर उन्होंने आवेदन किया और स्वीकृति के बाद उनके बैंक खाते में प्रतिमाह 1,000 रुपये की राशि मिलने लगी। यह राशि भले ही छोटी प्रतीत हो, लेकिन ओमलता के लिए यह आत्मनिर्भरता का आधार बनी। इस सहयोग से वह घर के छोटे-छोटे खर्च स्वयं वहन करने लगीं। अब उन्हें अपनी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। धीरे-धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा और जीवन में स्थिरता आई। ओमलता बताती हैं कि अब तक उन्हें योजना के तहत लगभग 22 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। वे आत्मविश्वास के साथ कहती हैं कि एक ग्रामीण महिला होते हुए भी आत्मनिर्भर बनी हैं। ओमलता कहती है कि महतारी वंदन योजना ने मेरे जैसे कई महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनने का अवसर दिया है इसके लिए मै मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करती हूं।

पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक आज

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत कुमार सिंह ने बताया है कि जिले में पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 की धारा 17 की उपधारा (5) के अंतर्गत जिला सलाहकार के रूप में जिला सलाहकार समिति का गठन किया गया है। उक्त सलाहकार समिति की बैठक 23 दिसम्बर 2025 को समय-सीमा की बैठक पश्चात संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला सलाहकार समिति के सदस्यों को नियत तिथि व समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया है।

रेल संघर्ष समिति चलाएगी चरणबद्ध आंदोलन, बनी रणनीति

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। अंबिकापुर-दिल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के बिश्रामपुर स्टेशन में ठहराव की मांग को लेकर रेल संघर्ष समिति ने चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय रविवार को अग्रसेन भवन बिश्रामपुर में आयोजित रेल संघर्ष समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में श्रम कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शफी अहमद, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य सुभाष गोयल, भाजपा नेता बनारसी जायसवाल, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष खजान चंद्र जिंदल सहित भाजपा एवं कांग्रेस के अनेक नेता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में बिश्रामपुर स्टेशन पर दिल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस के स्टॉपेज की मांग को जायज ठहराते हुए व्यापक जनसमर्थन जुटाने पर जोर दिया।कांग्रेस नेता शफी अहमद ने कहा कि कोयलांचल क्षेत्र होने के कारण बिश्रामपुर एक बड़ा क्षेत्र है, जहां देश के लगभग सभी प्रांतों के लोग निवास करते हैं, जिन्हें किसी भी कार्य के सिलसिले में दिल्ली आना जाना लगा रहता है

लेकिन ट्रेन के शुरू हुए तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया बिश्रामपुर समेत आसपास की बड़ी आबादी को इस ट्रेन सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से सटा होने के कारण बिश्रामपुर स्टेशन तक पहुंचना आसान है, जबकि आसपास के अन्य स्टेशन सड़क मार्ग से अंदर स्थित हैं, जहां आवागमन में कठिनाई होती है। इस दृष्टि से बिश्रामपुर स्टेशन में ट्रेन का ठहराव पूरी तरह उचित है। बैठक को राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य सुभाष गोयल सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि रेल संघर्ष समिति सांसद चिंतामणि महराज से मुलाकात कर अपनी मांग रखेगी। साथ ही रेलवे के डीआरएम एवं जीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा।समिति ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों का घेराव, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, ट्रेनों को काला झंडा दिखा प्रदर्शन, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना तथा आवश्यकता पड़ने पर सड़क जाम जैसे आंदोलनात्मक कदम शामिल होंगे।

बैठक में यह भी तय किया गया कि 27 दिसंबर को बस स्टैंड में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित कर आम नागरिकों को आंदोलन से जोड़ा जाएगा। बैठक में अशोक गुप्ता, नरेंद्र जैन, ललित गोयल, रमेश दनोदिया, प्रदीप गर्ग, विनय राणा, अशोक अग्रवाल शोक्की, विनोद जिंदल, दीपेंद्र सिंह चौहान, अनुपम फिलिप, कृष्ण गोयल, शशि नानू, अशोक जिंदल, प्रदीप अग्रवाल, वीरेश सिंह, सन्नी अग्रवाल, रिंकू गोयल, राकेश प्रजापति, रविशंकर, रोमी मखीजा, विजय गोयल, जतिन तायल, लखन लाल कुर्रे, मंजीत भामरा सहित अन्य उपस्थित थे।

वास्तविक किसानों से ही हो धान खरीदी, अवैध धान आवक रोकने सतत मॉनिटरिंग के निर्देश

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा के निर्देशन में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्री आर. एस. लाल एवं श्री चेतन बोरघरिया के द्वारा धान खरीदी के संबंध में खरीदी प्रभारी एवं नोडल अधिकारी की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक के दौरान जिले में चल रही धान खरीदी की प्रगति, व्यवस्थाओं, किसानों को हो रही सुविधाओं एवं संभावित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप धान खरीदी पूरी तरह पारदर्शी, सुव्यवस्थित हो तथा वास्तविक किसानों से ही खरीदी की जाए। किसी भी स्थिति में बिचौलियों या अपात्र व्यक्तियों से धान की खरीदी न हो। अवैध धान की

खरीदी प्रभारी एवं नोडल अधिकारी की हुई समीक्षा बैठक

आवक को लेकर निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रमुख मार्गों पर सख्त निगरानी रखें, ताकि बाहर से अवैध रूप से लाए जा रहे धान को रोका जा सके।

अपर कलेक्टर श्री बोरघरिया ने कहा कि धान उपार्जन केंद्रों पर सतत मॉनिटरिंग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक केंद्र पर धान की आवक, तौल, भंडारण एवं परिवहन की नियमित निगरानी रखें। संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दें ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी उपार्जन केंद्र पर बिचौलियों की संलिप्तता या अवैध धान खरीदी की शिकायत मिलती है, तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी को शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और सुचारू रूप से धान खरीदी के निर्देश दिए।

बैठक में खाद्य अधिकारी श्री विनय कुजूर, जिला विपणन अधिकारी सुश्री प्रीतिका पूजा केरकेट्टा, सहायक पंजीयक सहकारिता श्री एस.के. पैंकरा उपस्थित रहे।

प्रशासन गाँव की ओर के तहत शिविर आयोजित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रशासन गाँव की ओर थीम को लेकर सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। शिविर 25 दिसम्बर तक चलेगा। कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस वीक ''प्रशासन गांव की ओर 2025'' अंतर्गत जनपद पंचायत एवं ग्राम

पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें प्राप्त आवेदनो का निराकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं के तहत लाभान्वित करते हुए सामग्रियों का वितरण भी किया जा रहा है। सुशासन सप्ताह अंतर्गत जन-शिकायतों की अधिकतम संख्या को निपटाने के लिए सरकार की पहल है और सुशासन सप्ताह मनाने का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जनता की प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाना है। सप्ताह के दौरान जनकल्याण अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे शिविरों में आमजन की समस्याओं, सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण तथा योजनाओं से अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा के मार्गदर्शन में सुशासन सप्ताह के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की गई है। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों और वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में अधिक से अधिक नागरिकों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। साथ ही उन्हें शासन की विभिन्न सेवाएं समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाएंगी और शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।

बिजली की मांग, हड़ताल का 8वां दिन, आंदोलनकारियों ने मुंडन कराकर दिया धरना

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

चांदनी बिहारपुर। सूरजपुर जिले के वनांचल एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र चांदनी बिहारपुर में वर्षों से लंबित बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन अब आर-पार की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल आठवें दिन भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। आंदोलनकारियों ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि जब तक बिजली की मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हों। इस आंदोलन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि क्षेत्र की 17 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 26 आश्रित ग्रामों के लगभग 20 हजार ग्रामीण आज भी अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। बिजली के अभाव में बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं की सुरक्षा, मोबाइल नेटवर्क, रोजगार और दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के दशकों बाद भी उन्हें बिजली जैसी मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड, सीमित संसाधन और प्रशासनिक उपेक्षा के बावजूद आंदोलनकारियों का हौसला कमजोर नहीं पड़ा है। हड़ताल स्थल पर युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और छात्र बड़ी संख्या में डटे हुए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने हक और सम्मान के लिए है। आंदोलन को प्रभावी और संवेदनशील बनाने के लिए ग्रामीणों द्वारा शांतिपूर्ण लेकिन प्रतीकात्मक विरोध अपनाया जा

रहा है। हड़ताल के सातवें दिन आंदोलनकारियों ने रामायण कीर्तन कार्यक्रम आयोजित कर शासन-प्रशासन का ध्यान अपनी पीड़ा की ओर आकर्षित किया। कीर्तन के माध्यम से ग्रामीणों ने धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से यह संदेश दिया कि उनका संघर्ष न्यायपूर्ण है। आठवें दिन आंदोलनकारियों ने प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ सिर मुंडवाकर अनोखा और भावनात्मक विरोध दर्ज कराया। मुंडन करने वाले कार्यकताओं ने कहा कि यह उनका अंतिम विकल्प नहीं, बल्कि वर्षों से अनसुनी पीड़ा का प्रतीक है। उनका कहना है कि हर बार केवल आश्वासन मिला, लेकिन जमीन पर बिजली आज तक नहीं पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली समस्या से दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन पूरी तरह अवगत हैं, इसके बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय या कार्ययोजना सामने नहीं आई है। इसी कारण ग्रामीणों को मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र विद्युत विस्तार कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, तो आंदोलन को और अधिक व्यापक और तीव्र किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। फिलहाल चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है और पूरे जिले की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

उटपटांग बयानबाजी से भड़के आंदोलनकारी

बताया गया है कि भाजपा नेता उटपटांग बयान दे रहे है जिससे आंदोलनकारी भड़क गए है आंदोलन से जुड़े युवा अब आर-पार की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे है। बहरहाल अब तक ग्रामीणों की बिजली विस्तार की मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिसको लेकर आज धरने पर बैठे तुलसीराम जायसवाल उपसरपंच, गजमोचन सिंह सरपंच संघ अध्यक्ष, जितेंद्र साकेत, लक्ष्मण जायसवाल, रामराज सिंह, भानुप्रताप खैरवार ने अपना सर मुंडन संस्कार करवाकर विरोध प्रदर्शन किया और मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराया है।

महीनों से लंबित समस्या का मंत्री लक्ष्मी ने कराया मौके पर समाधान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की संवेदनशीलता और त्वरित कार्यशैली एक बार फिर सामने आई, जब उन्होंने महीनों से परेशान एक पीड़ित महिला की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान सुनिश्चित कराया। नोनी सुरक्षा योजना से संबंधित दस्तावेजों में पीड़ित महिला अपनी भतीजी के नाम में सुधार कराने के लिए महीनों से विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। आज रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीड़ित महिला की मुलाकात मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े से हुई। मंत्री जी ने महिला की पीड़ा को संवेदनशीलता के साथ सुना और तुरंत मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारी को फोन कर समस्या के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने उन अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाने को कहा, जिनकी निष्क्रियता के कारण महिला को महीनों तक परेशान होना पड़ा। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो, जिसमें मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े फोन पर अधिकारियों से बात करती नजर आ रही हैं, उनके ममतामयी, दृढ़ और जनहितकारी नेतृत्व का सशक्त उदाहरण है।

किसान जगदीश सिंह ने किसानों को मिल रही व्यवस्था पर जाहिर की संतुष्टि

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। जिले के धान उपार्जन केन्द्रों में लागू पारदर्शी और सुव्यवस्थित व्यवस्था से किसानों को धान विक्रय में बड़ी राहत मिली है। अम्बिकापुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सरगंवा के निवासी किसान जगदीश सिंह ने बताया कि इस वर्ष धान की उपज अच्छी हुई है। उन्होंने कुल 70.80 क्विंटल धान रकबा है। उन्होंने बताया कि नमनाकला धान उपार्जन केन्द्र से अपना टोकन कटवाया। पहले चरण में 46 क्विंटल धान का टोकन कटा, जिसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। उपार्जन केन्द्र

पहुंचते ही गेट पास, नमी परीक्षण की प्रक्रिया त्वरित रूप से पूरी की गई और तत्काल बारदाना उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि धान विक्रय की पूरी प्रक्रिया सरल, सुगम और व्यवस्थित रही। केन्द्र में किसानों के लिए पेयजल एवं बैठने जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। किसान जगदीश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में धान का 3100 रुपये प्रति क्विंटल का सर्वाधिक समर्थन मूल्य मिल रहा है, जिससे किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है। धान विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग वे गेहूं, सरसों, सब्जी सहित अन्य फसलों की खेती में कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। उन्होंने धान खरीदी व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि यह व्यवस्था बहुत अच्छी है और इससे किसान बेहद खुश हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया।

कुनकुरी नगर पंचायत को सीएम साय ने दी 107.32 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक विकास सौगात

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के कुनकुरी नगर पंचायत क्षेत्र को 107 करोड़ 32 लाख रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्वीकृति देकर मुख्यमंत्री ने नगर को ऐतिहासिक सौगात दी है। इन योजनाओं से कुनकुरी नगर की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन, यातायात और नागरिक सुविधाओं में व्यापक और दीर्घकालिक सुधार होगा। कुनकुरी नगर में युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 63 करोड़ 84

लाख रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह कॉम्प्लेक्स क्षेत्रीय युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने नगर पंचायत क्षेत्र में 53 विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति देकर जनता से किए गए अपने वादे को पूरा किया है। इन कार्यों से नगर के विभिन्न वार्डों और मोहल्लों में बुनियादी सुविधाएं सुदृढ़ होंगी और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुनकुरी को बड़ी सौगात देते हुए 2 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से नेचुरोपैथी भवन निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और योग को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिकों को बेहतर वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। पर्यटन और धार्मिक आस्था को सशक्त करने के लिए छठ घाट के समग्र विकास हेतु 5 करोड़ 17 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। घाट के सौंदर्यीकरण और विकास से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों मंक वृद्धि होगी। कुनकुरी नगर में सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के लिए 6 करोड़ 67 लाख रुपये की लागत से आधुनिक बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम भवन का निर्माण किया जाएगा, जिससे कला, संस्कृति और सामाजिक आयोजनों को नया मंच मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती लाने के उद्देश्य से नालंदा परिसर के 250 सीटर विस्तार के लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होगा। नगर के यातायात को सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए 7 करोड़ 26 लाख रुपये की लागत से हाई-टेक बस स्टैंड के निर्माण को मंजूरी मिली है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

जायसवाल समाज की बैठक में सर्वसम्मति से वीरेंद्र को चुना गया जिलाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां सर्किट हाउस में जयसवाल समाज की जिला स्तरीय बैठक आहूत की गई। जिसमे जिले के सभी विकासखण्डो से समाज के वरिष्ठजन उपस्थित हुए। इस दौरान सर्वसम्मति से वीरेंद्र जायसवाल प्रेमनगर को जिला अध्यक्ष चुना गया है। समाज के उत्थान के लिए सभी विकास खण्डो से प्रभारी भी बनाया गया, जिसमें प्रतापपुर से नवीन जायसवाल व शिव शंकर जायसवाल, सूरजपुर से रामानंद जायसवाल एवं सत्यनारायण जायसवाल, भैयाथान से विनय जायसवाल, आशीष जायसवाल, एवं सुरेश जयसवाल, रामानुजनगर से अशोक जायसवाल एवं महेश जयसवाल, प्रेमनगर से संतोष जायसवाल एवं

मिथलेश जायसवाल, बिहारपुर से लल्लू जायसवाल एवं रामपाल जायसवाल, ओड़गी से दिवाकर जायसवाल एवं रामदास जायसवाल को प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। जिला अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रभारियों को मिलकर सभी विकास खण्डो में समाज के उत्थान के लिए बैठक आयोजित करने को कहा गया। इस दौरान वीरेंद्र जायसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे पूर्वज पहले राजाओं के वंशज थे लेकिन आज हम लोगों में एकता और मतभेद होने के कारण हम बिखर कर रह गए हैं, उन्होंने राजनीति से हटकर समाज के हित में कार्य करने को कहा, संबोधन की अगली कड़ी में शशि भूषण जायसवाल रामानंद जायसवाल सत्यनारायण जायसवाल नवीन जायसवाल, अशोक जायसवाल ने भी अपने उद्बोधन में कहा की हम संगठित होंगे तभी हम समाज के लिए कार्य कर सकेंगे अतः इसके लिए कार्यकारिणी का गठन हो और सभी विकासखण्डो में बैठक आयोजित कर जयसवाल समाज को जोड़ने का प्रयास किया जाए। बैठक में उपस्थित सभी ने सर्वसम्मति से एकजुट होकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करने की सहमति प्रदान की है। बैठक में, शिवशंकर जायसवाल, डॉ. निलेश जायसवाल, मिथलेश जायसवाल, राकेश जायसवाल, संजय जायसवाल, मनोज जायसवाल, आशीष जायसवाल, महेश जयसवाल, आनंदपाल जायसवाल, राहुल जायसवाल, रमेश जायसवाल, विनय जायसवाल, लल्लू जायसवाल, विवेक जायसवाल, संतोष जायसवाल, अशोक जायसवाल, रामसूरत जायसवाल, राजेश जायसवाल, अमन जयसवाल, गणेश जायसवाल, राजेंद्र जायसवाल, प्रेम जयसवाल, शिव शंकर जायसवाल सुशील राय, संतोष जायसवाल, सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विनय जायसवाल एवं आभार प्रदर्शन राकेश जायसवाल ने किया।

ईओडब्ल्यू के 3800 पन्नों का चालान से बढ़ीं चैतन्य बघेल की मुश्किलें

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने उनके खिलाफ कोर्ट में 3800 पन्नों का आठवां पूरक चालान पेश किया है। इस चालान में दावा किया गया है कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े लेन-देन में 200 से 250 करोड़ रुपये की राशि मिली है। ईओडब्ल्यू के अनुसार यह खुलासा सौम्या, अरुणपति, अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के बीच हुए व्हाट्सऐप चैट की जांच के बाद हुआ है। नए तथ्यों के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि चैतन्य बघेल को फिलहाल जेल से राहत मिलना मुश्किल है।

व्हाट्सऐप चैट से सामने आए अहम सबूत

जांच एजेंसियों का आरोप है कि चैतन्य बघेल ने शराब माफियाओं की मदद से करीब 1000 करोड़ रुपये की ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने में भूमिका निभाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक इस पूरे अवैध कारोबार से उन्हें करीब 16 करोड़ रुपये का सीधा फायदा हुआ, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने बिजनेस सेटअप में किया।

शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय गणित दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर में गणित विभाग द्वारा राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 का आयोजन 17 दिसंबर से 22 दिसंबर 2025 तक किया गया। यह कार्यक्रम सीजीकॉस्ट, एनसीएसटीसी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित हुआ। कार्यक्रमों का आयोजन महाविद्यालय के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 17 दिसंबर को उद्घाटन सत्र एवं परिचयात्मक व्याख्यान के साथ हुआ। इस दौरान छात्राओं को गणित के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया गया तथा इस शून्य से अनंत तकः भारतीय गणित की

विरासतह्वविषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। 19 दिसंबर को विशेषज्ञों द्वारा दैनिक भारतीय जीवन में गणितह्व विषय पर सारगर्भित व्याख्यान दिया। इसी दिन भारतीय गणितज्ञों एवं उनके योगदान पर आधारित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन पर आधारित चलचित्र का प्रदर्शन भी किया गया। 20 दिसंबर को छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु भाषण प्रतियोगिता एवं रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। भाषण प्रतियोगिता का विषय रामानुजन का योगदान एवं भारतीय सभ्यता में गणितह्व रहा, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। वहीं रंगोली सममितिह्व विषय पर आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में गणित और कला का सुंदर समन्वय देखने को मिला। कार्यक्रम के अंतिम दिन 22 दिसंबर को मंदिर स्थापत्य में ज्यामितिह्व विषय पर मॉडल एवं पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं ने भारतीय वास्तुकला में निहित गणितीय सिद्धांतों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात प्राचीन भारतीय ग्रंथों में गणितः शुल्ब सूत्र से खगोल विज्ञान तक तथा शून्य से अनंत तकः भारतीय गणित की विरासत विषय पर व्याख्यान दिए गए। कार्यक्रम का समापन प्रमाण पत्र वितरण के साथ हुआ। राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 का यह आयोजन भारतीय गणितीय विरासत को समझने एवं गणित के प्रति रुचि विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ।

भाजपा से प्रभावित 4 सरपंच अपने समर्थकों के साथ विधायक भूलन के समक्ष थामा भाजपा का दामन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली व नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के चार सरपंचों ने पंच एवं बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ विधायक भूलन सिंह मरावी के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिया है। भाजपा में शामिल होने वाले सरपंचों में ग्राम पंचायत लाछा की इजोरिया सिंह, झांसी के मदन सिंह, पीढ़ा के उमेश सिंह एवं कुरुवां के सरपंच अनेश टोप्पो शामिल है जिन्होंने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रवेश करने वाले सरपंचों एवं उनके समर्थकों को विधायक श्री मरावी द्वारा भगवा गमछा भेंटकर मुंह मीठा कराकर विधिवत भाजपा प्रवेश कराया गया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रेमनगर विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भाजपा का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जनकल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रहित की नीति से प्रभावित होकर आज सरपंच एवं ग्रामीण संगठन से जुड़ रहे हैं, जो पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शार्ता है। विधायक मरावी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज देश प्रदेश में ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं, जिन्हें पहले असंभव माना जाता था। उन्होंने भाजपा में शामिल हुए सभी सरपंचों एवं कार्यकताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनके जुड़ने से संबंधित गांवों और क्षेत्रों के विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने सरपंचों से निरंतर संवाद बनाए रखने और विकास से जुड़े कार्यों की जानकारी सीधे देने की भी अपील की। इस अवसर पर भाजपा जिला प्रभारी शिवनाथ यादव, जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी, वरिष्ठ नेता भीमसेन अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष रामकृपाल साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंच संचालन भाजपा जिला महामंत्री शशिकांत गर्ग ने किया। इस दौरान संत सिंह, संदीप अग्रवाल, अरविंद मिश्रा, विजय नारायण राजवाड़े, सुरेंद्र राजवाड़े, अजय अग्रवाल (अज्जू), नीरज कुमार गुप्ता, पवन साहू, संजू सोनी, तिलक राजवाड़े, सतवीर सिंह, कौशल गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

एसआईआर के बाद छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में कल जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग मंगलवार को केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इसे 2026 में प्रस्तावित विधानसभा और अन्य चुनावों की तैयारियों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा। राजनीतिक दल तय समय सीमा के भीतर मतदाता सूची पर दावे, आपत्तियां और सुझाव दर्ज करा सकेंगे। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि दलों को मतदाता सूची की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाए।

केंद्र सरकार का 'विकसित भारत- जी राम जी' बिल आखिर संसद में पारित हो गया। सत्ता पक्ष का तर्क है कि मनरेगा में समय के साथ कई संरचनात्मक खामियां पैदा हो गई थीं, जिनका लाभ भ्रष्ट तत्वों ने उठाया। नए विधेयक के जरिए सरकार मजदूरों को अधिक काम, बेहतर भुगतान व्यवस्था और पारदर्शिता देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब काम की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, तो यह मजदूरों के लिए सकारात्मक कदम होगा। उधर, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इसके नाम परिवर्तन पर विरोध जताया है। कांग्रेस का आरोप है कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना राष्ट्रपिता का अपमान है। वहीं, विपक्ष ने यह आशंका भी जताई कि धीरे-धीरे यह योजना अपने मूल स्वरूप से दूर हो जाएगी और भविष्य में इसे समाप्त करने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। अब असली परीक्षा इस बात की होगी कि क्या गरीब मजदूर को नियमित काम, समय पर भुगतान और सम्मानजनक मजदूरी मिल पाती है या नहीं। फिलहाल, संसद की बहस और राजनीतिक घमासान के बीच देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। इसी मुद्दे का विश्लेषण करता *आजकल* का यह खास अंक...

भरोसे की कसौटी पर 'जी राम जी'

विश्लेषण

सुशील देव

वरिष्ठ स्तंभकार

आखिरकार लंबी और तीखी राजनीतिक बहस के बाद 'जी राम जी' विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। मजदूरों के हित में लाए गए इस विधेयक को केंद्र सरकार मनरेगा का उन्नत और पारदर्शी विकल्प बता रही है, जबकि विपक्ष इसे एक लोकप्रिय योजना को कमजोर करने और महात्मा गांधी के नाम को हटाने का राजनीतिक प्रयास मान रहा है। संसद के भीतर और बाहर जिस तरह का शोर, धक्का–मुक्की और आरोप–प्रत्यारोप देखने को मिले, उसने यह साफ कर दिया कि यह केवल एक प्रशासनिक सुधार का मुद्दा नहीं, बल्कि विचारधारा और राजनीति से भी गहराई से जुड़ा विषय है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि 'विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025' के जरिए सरकार मजदूरों को अधिक काम, बेहतर भुगतान व्यवस्था और पारदर्शिता देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि मनरेगा में समय के साथ कई संरचनात्मक खामियां पैदा हो गई थीं, जिनका लाभ भ्रष्ट तत्वों ने उठाया। अनियमितताएं बढ़ीं।

> **मजदूरों के हित में लाए गए 'विकसित भारत जी राम जी विधेयक को केंद्र सरकार मनरेगा का उन्नत और पारदर्शी विकल्प बता रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकप्रिय योजना को कमजोर करने और महात्मा गांधी के नाम को हटाने का राजनीतिक प्रयास मान रहा है। संसद के भीतर और बाहर जिस तरह का शोर और आरोप–प्रत्यारोप देखने को मिले, उसने यह साफ कर दिया कि यह केवल एक प्रशासनिक सुधार का मुद्दा नहीं, बल्कि विचारधारा और राजनीति से भी गहराई से जुड़ा विषय है। उम्मीद करें कि मेहनतकश व्यक्ति को उनका सम्मानजनक रोजगार और सुरक्षित भविष्य मिलेगा।**

नाम परिवर्तन पर विपक्ष नाराज

मजदूरी और निर्माण सामग्री के अनुपात में गड़बड़ी, फर्जी जॉब कार्ड, भुगतान में देरी और राज्यों में धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लंबे समय से सामने आते रहे हैं। सरकार का कहना है कि नए विधेयक में तकनीक, निगरानी और जवाबदेही को मजबूत किया गया है, ताकि गरीब मजदूर तक योजना का वास्तविक लाभ पहुंचे।

वहीं विपक्ष की आपत्ति का केंद्र केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि नाम परिवर्तन भी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार योजनाओं के नाम बदलने में ज्यादा रुचि रखती है, बजाय उनके प्रभावी क्रियान्वयन के। उनका कहना है कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि उस विचारधारा को कमजोर करने का प्रयास है, जो गांव, श्रम और आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखती है। विपक्ष ने यह आशंका भी जताई कि धीरे-धीरे यह योजना अपने मूल स्वरूप से दूर हो जाएगी और भविष्य में इसे समाप्त करने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। इसी कारण विपक्ष ने विधेयक को स्थायी समिति में भेजने की मांग की, ताकि विस्तृत चर्चा और संशोधन हो सकें, लेकिन यह मांग लोकसभा में खारिज कर दी गई। सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों का तीखा जवाब दिया।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ी

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया, जबकि उनके आदर्शों को जमीन पर लागू नहीं किया। उन्होंने याद दिलाया कि मनरेगा का मूल नाम 'नरेगा' था और 2009 के चुनाव से पहले इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया।

सरकार का दावा है कि मोदी सरकार ने गांधी के ग्राम स्वराज, स्वावलंबन और श्रम की गरिमा के विचारों को वास्तविक नीतियों में उतारने का प्रयास किया है। चौहान ने आंकड़ों के जरिए यह भी बताया कि कांग्रेस शासन के दौरान जहां 1660 करोड़ श्रम दिवस सृजित हुए, वहीं मौजूदा सरकार के दौरान यह आंकड़ा 3210 करोड़ तक पहुंचा। महिलाओं की भागीदारी भी 48 प्रतिशत से बढ़कर 56.73 प्रतिशत होने का दावा किया गया। सरकार की एक बड़ी दलील यह भी रही कि मनरेगा में मजदूरी और सामग्री खर्च का संतुलन कई राज्यों में बिगड़ा हुआ था। नियमों के अनुसार जहां 60 प्रतिशत राशि मजदूरी पर खर्च होनी चाहिए थी, वहां कई राज्यों में यह अनुपात कम कर दिया गया और सामग्री पर बेहद कम खर्च दिखाया गया। इससे न केवल काम की गुणवत्ता प्रभावित हुई, बल्कि भ्रष्टाचार के रास्ते भी खुले।

लूट-खसोट पर लगाम लगेगी

सरकार का कहना है कि 'जी राम जी' विधेयक में इन खामियों को दूर करने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं और तकनीकी निगरानी से लूट-खसोट पर लगाम लगेगी। हालांकि विपक्ष का यह सवाल भी वाजिब है कि किसी योजना की आत्मा केवल नियमों से नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और ईमानदार क्रियान्वयन से तय होती है। मनरेगा ने अपने शुरुआती वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल दिया, पलायन को रोका और संकट के समय लाखों परिवारों के लिए सुरक्षा कवच का काम किया। कोरोना काल में भी इस योजना ने ग्रामीण भारत को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में विपक्ष का डर है कि बदलाव की आड़ में यदि योजना की पहुंच या अधिकार कमजोर हुए, तो इसका सीधा असर सबसे गरीब वर्ग पर पड़ेगा। विपक्ष दलों ने संसद से सड़क तक इस विधेयक को लेकर विरोध जताया। कहा, महात्मा गांधी का नाम हटाकर सरकार ने उचित नहीं किया। विपक्ष ने इसे गांधी का अपमान भी बताया। सच यह भी है कि मनरेगा जैसी बड़ी योजना में खामियां रही हैं और कुछ राज्यों में केंद्र व राज्य-दोनों की जिम्मेदारी तय होती है। भुगतान में देरी, काम की उपलब्धता और निगरानी की समस्याएं वास्तविक रही हैं।

अब 125 दिन काम की गारंटी

यदि नया विधेयक इन समस्याओं को दूर करता है और सरकार का यह दावा सही साबित होता है कि अब काम की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, तो यह मजदूरों के लिए सकारात्मक कदम होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पारदर्शिता केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर भी दिखे। आखिरकार 'जी राम जी' विधेयक केवल नाम परिवर्तन या राजनीतिक जीत–हार का मुद्दा नहीं होना चाहिए। यह करोड़ों ग्रामीण मजदूरों की रोजी–रोटी से जुड़ा सवाल है। सत्ता पक्ष और विपक्ष-दोनों को चाहिए कि वे जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय इसके क्रियान्वयन पर नजर रखें।

सुरक्षित भविष्य की उम्मीद

यदि सरकार वास्तव में गांधी के आदर्शों को जीवित रखने और विकसित गांव की नींव पर विकसित भारत बनाने का दावा कर रही है, तो उसे इस विधेयक को पूरी ईमानदारी से लागू करना होगा। वहीं विपक्ष की भूमिका भी केवल विरोध तक सीमित न रहकर रचनात्मक सुझाव देने की होनी चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए नाम और नए ढांचे के साथ यह योजना मजदूरों के काम के अधिकार को मजबूत करेगी, गांवों में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देगी और राजनीति से ऊपर उठकर उस उद्देश्य को पूरा करेगी। उम्मीद करनी चाहिए कि मेहनतकश व्यक्ति को उनका सम्मानजनक रोजगार और सुरक्षित भविष्य मिलेगा।

नाम बदलने के साथ हकीकत भी बदले

नई योजना

रवि शंकर

स्वतंत्र पत्रकार

शेक्सपियर के मशहूर नाटक रोमियो एंड जूलियट की एक लाइन है, जिसका अर्थ है- नाम में क्या रखा है। आज अगर शेक्सपियर होते तो भारत की संसद उन्हें बताती कि शेक्सपियर महोदय, नाम में बहुत कुछ रखा है। संसद अब सिर्फ नाम पर ही बहस करेगी क्योंकि मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार द्वारा लाई गई योजना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) का नाम बदलकर विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी राम जी) कर दिया है। बहरहाल, विपक्ष ने इसका विरोध बिल के प्रावधानों के साथ ही ये कहकर भी किया कि महात्मा गांधी का नाम हटाना राष्ट्रपिता का अपमान है। ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार पुरानी योजनाओं की जगह नए नाम के साथ स्कीम लाई हो। योजनाओं के नाम के साथ ही शहरों के नाम, सड़कों के नाम, जगहों के नाम बदले गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि 1975 से 2013 के बीच शुरू की गई 32 योजनाओं को मोदी सरकार ने नाम बदलकर लॉन्च किया। वह सरकार पर पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग और रीब्रैंडिंग का इल्जाम लगाती रही है। गांधीजी का नाम हटाना उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश है। सिर्फ नाम बदलकर क्रेडिट लेने की मांग है जबकि पहले मोदीजी इसे फेलियर का स्मारक कहते थे। जबकि सरकार का कहना है कि यह विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा है और गांधीजी के विचारों से कोई विरोध नहीं है। नए कानून की सबसे बड़ी घोषणा है कि ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले गारंटीड रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए जाएंगे। 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलने से उनकी आय में इजाफा होगा, साथ ही रोजगार सृजन के नए तरीके विकसित होंगे। पहली नजर में यह फैसला राहत भरा लगता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा बदलाव भी जुड़ा है। अब इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार नहीं उठाएगी। राज्यों को 10 से 40 प्रतिशत तक खर्च अपनी जेब से देना होगा। यानी जहां पहले मनरेगा पूरी तरह केंद्र प्रायोजित योजना थी, अब राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है। जमीनी हकीकत यही है कि गरीब राज्य यह योजना लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास वित्तीय बोझ उठाने की क्षमता नहीं होगी और केन्द्र ने पहले ही खुद को यह कहकर निकल लेने का जुगाड़ कर लिया है। 'जी राम जी' बिल में एक और अहम प्रावधान है। बुवाई और कटाई के मौसम के दौरान करीब 60 दिन तक इस योजना के तहत काम नहीं दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे खेती के समय मजदूरों की कमी नहीं होगी और किसान परेशान नहीं होंगे। विपक्ष का कहना है कि इससे गरीब मजदूरों को महीनों तक काम से वंचित रहना पड़ेगा। वहीं, मोदी सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने और रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने का फैसला पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए भी अहम माना जा रहा है।

> ***असली परीक्षा इस बात की होगी कि क्या गरीब मजदूर को नियमित काम, समय पर भुगतान और सम्मानजनक मजदूरी मिल पाती है या नहीं। फिलहाल, देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है।***

अब नए बिल से सरकार विपक्ष के इस आरोप का जवाब देने की कोशिश करेगी। यह योजना बीजेपी और पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी के बीच राजनीतिक विवाद का मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि केंद्र ने कथित वित्तीय अनियमितताओं का हवाला देते हुए 2022 से पश्चिम बंगाल को निधि देना रोक रखा था। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले कुछ वर्षों में, सरकार मांग के अनुरूप 100 दिनों का काम उपलब्ध कराने के अनिवार्य दायित्व के बावजूद, प्रति वर्ष 50-55 दिनों से ज्यादा काम उपलब्ध कराने में लगातार विफल रही है। यह स्थिति तब है जब नौकरियों की मांग लगातार बढ़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों का संकट और ज्यादा गहराया है। दूसरी तरफ, मनरेगा के लिए बजट आवंटन में लगातार कटौती की गई है। मनरेगा का उद्देश्य केवल रोजगार प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, तालाब निर्माण और वृक्षारोपण जैसी अवसंरचनात्मक परियोजनाएं कराकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना भी है। बेशक, 'जी राम जी' के नाम, काम के दिन और ढांचे में बदलाव जरूर बड़ा है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या इससे गांवों में रोजगार की स्थिति सच में सुधरेगी। अनुभव बताता है कि सिर्फ नाम बदलने और कागजी गारंटी बढ़ाने से जमीन पर बदलाव नहीं आता। असली परीक्षा इस बात की होगी कि क्या गरीब मजदूर को नियमित काम, समय पर भुगतान और सम्मानजनक मजदूरी मिल पाती है या नहीं। फिलहाल, संसद की बहस और राजनीतिक घमासान के बीच देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है।

उपयोगी सिद्ध होगी केंद्र सरकार की योजना

सार्थकता

विकेश कुमार बडोला

स्वतंत्र स्तंभकार

देश के अधिसंख्यक नागरिकों, मतदाताओं व लोगों की दृष्टि में अस्तित्वहीन विपक्ष के अति अराजक प्रतिरोध के बाद अंततः 18 दिसंबर 2025 को 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025' लोकसभा में अधिमतों के साथ पारित हो गया। एक दिन पूर्व सभासदन में इस विधेयक पर व्यापक चर्चा हुई। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शीतकालीन सत्र में संसदीय पटल पर रखा गया विधेयक कांग्रेस समेत अन्य दलों के सांसदों को रास नहीं आया। विपक्ष का विरोधी आचरण मात्र विरोध के लिए दिखाई दिया।

विपक्षी सांसदों ने जो बातें उठाईं, उनकी कहीं कोई सार्थक उपयुक्तता नहीं दिखाई दी। उल्लेखनीय है कि पारित विधेयक 25 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का स्थान लेगा। हल्ला करने, बड़बोला आचरण दिखाने तथा देश के सभ्य नागरिकों की दृष्टि में स्वयं को अधिक से अधिक पतित करते हुए कहने को तो विपक्ष मनरेगा के नाम परिवर्तन को महात्मा गांधी के अपमान से जोड़ रहा है, पर विचार करने वाली बात ये है कि अखिल भारतीय रोजगार गारंटी की योजना का अपेक्षित क्रियान्वयन किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़े रहने से होगा अथवा वर्तमान सत्ता, शासन-प्रशासन द्वारा लोकतांत्रिक निष्ठा के साथ इसके उपयोगी अद्यतनीकरण से होगा। विधेयक के महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक है रोजगार दिवसों में 100 के स्थान पर 125 दिवसों की वृद्धि। मनरेगा को जी राम जी नाम के साथ अद्यतन करने वाले विधेयक पर सामान्य नागरिकों की पहली प्रतिक्रिया तो यही होगी कि यह इतना गंभीर विषय नहीं था, जो संसद से लेकर सड़क तक विरोध के नाम पर विरोध करके फैलाया व उठाया जाए। कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार के दो पंचवर्षीय कार्यकाल में मनरेगा से जुड़ा भ्रष्टाचार आये दिन लोगों के बीच चर्चा का विषय हुआ करता था। लोग कैसे भूल सकते हैं कि केंद्रीय शासन-प्रशासन से लेकर ग्रामों के प्रधानों तक ने आभासी मनरेगा रोजगार दिखाकर करोड़ों की धनराशि का हेरफेर किया था। अवैध घुसपैठियों को मनरेगा रोजगार के पत्र मिले हुए थे। धरातल पर इनमें से कोई भी व्यक्ति कोई रोजगार या कार्य नहीं करता था, किंतु इनके नाम पर धनाबंटन होता रहा और अवैध तंत्र में ऊपर से नीचे तक परस्पर विभाजित होता रहा। इस समय भारतीय संसद में विपक्ष का अस्तित्व शून्यगति को प्राप्त है। बात यदि जनता के हित की है, तो वो भलीभांति अवगत है कि ग्रामीण विकास मंत्री के नेतृत्व में जी राम जी योजना लोकहित में परिष्कृत की जा रही है। परिवर्तनगामी मनरेगा द्वारा अपेक्षित जनकल्याणकारी लक्ष्य तो प्राप्त होंगे ही होंगे, साथ ही योजना की कमियों, दोषों तथा भ्रष्टाचार का भी निवारण हो सकेगा।

> ***परिवर्तनगामी मनरेगा द्वारा अपेक्षित जनकल्याणकारी लक्ष्य तो प्राप्त होंगे ही होंगे, साथ ही योजना की कमियों, दोषों तथा भ्रष्टाचार का भी निवारण हो सकेगा।***

ग्रामीण रोजगार योजना पर बने पक्ष-विपक्ष की सहमति

मुद्दा

योगेश कुमार सोनी

वरिष्ठ पत्रकार

मनरेगा पर एक बार फिर पक्ष-विपक्ष आमने-सामने आ गया। यह देश की एक बड़ी योजना है जो रीढ़ की हड्डी भी मानी जाती है और अब फिर से चर्चाओं में आ गई। मामला यह है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान मनरेगा कानून आया था। यूपीए सरकार ने 2005 में 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून' को लागू किया था और 2009 में इसके नाम के साथ 'महात्मा गांधी' जोड़ा गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मानी जाती है।

पिछले दो दशकों से मनरेगा ग्रामीण रोजगार की रीढ़ रही है लेकिन अब मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी 'वीबी-जी राम जी' बिल कर दिया है। संसद के दोनों सदन से यह बिल पास हो गया है लेकिन इसको विपक्ष के सवालों की बड़ी बौछार हो रही है। विपक्ष का कहना है कि इस अहम कानून में बदलाव करने के लिए जो राज्यों पर बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ डालेंगे तो यह योजना निश्चित तौर विफल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए पक्ष-विपक्ष को यह समझना चाहिए कि मनरेगा जैसी योजना पर राजनीति नही करनी चाहिए। चूंकि इस योजना से एक बड़ा वर्ग साधा जाता है। मनरेगा के मुख्य लाभों में अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, काम में लिंग-आधारित वेतन अंतर को खत्म करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आदि शामिल हैं। इन सब सुविधाओं व इसके लाभ लेने वाले वर्ग से यह तो तय हो जाता है कि इसमें कहीं भी राजनीति की जरूरत नहीं है। देश के उस वर्ग को लाभ देना जो जमीनी स्तर पर अपने काम से देश निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है,यह किसी भी सरकार का धर्म,फर्ज व कर्तव्य माना जाता है। यदि केवल नाम बदलने की बात है तो इसमें विपक्ष को हंगामा करने की जरूरत नहीं है। यदि सत्ताधारी पक्ष को इसमें

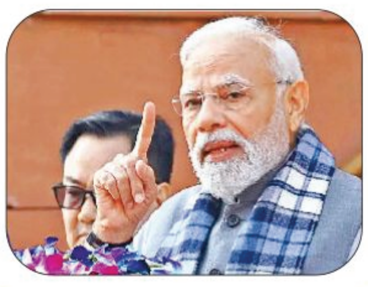

> **इस योजना की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। यदि विपक्ष इस योजना को लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है तो वह उस तरह के सुझाव दें जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले।**

कुछ बदलाव करने हैं तो वह इस तरह के बदलाव करे जिससे लाभकारियों को फायदा मिले और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए वहीं यदि विपक्ष इस योजना को लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है तो वह उस तरह के सुझाव दें जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले। राजनीति करने के लिए भारत जैसे देश में इतने मुद्दे हैं कि हर घंटे एक मुद्दे को उठाया या भुनाया जाए तो पक्ष-विपक्ष का पूरा वर्ष बीत जाएगा लेकिन कुछ मुद्दों पर केवल काम किया जाए वह बेहतर ही है। बीती कांग्रेस की सरकार में सैकड़ों योजनाएं लागू की गई थी, जिसमें जनता को लाभ भी मिला लेकिन हमेशा दलालों को बोलबाला रहता था। अब डिजिटल युग आने के बाद प्रक्रियाएं अपडेट व अपग्रेड हुई हैं लेकिन अब भी स्थिति पूर्ण रूप से लाभकारियों के नियंत्रण में नही है चूंकि किसी भी योजना के लिए लागू करने से ज्यादा उसके लिए जागरूक करना होता है।

कांग्रेस की ओर से बयान आया है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलने के साथ ही अब इसका बोझ राज्यों पर डाल दिया है। जो अधिकार पहले पंचायतों के पास थे, उन्हें अब छीनकर केंद्रीयकृत व्यवस्था को सौंपा जा रहा है। यह कदम महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है और कांग्रेस इसका सख्ती से विरोध करेगी। यह समझना चाहिए कि यदि मौजूदा सरकार किसी भी योजना में बदलाव करती है तो यह तय नहीं है कि वह उसमें जनहित का ख्याल नहीं रखती बल्कि उसको पहले से बेहतर करके लागू करती है। कांग्रेस इस मामले में जरूरत से ज्यादा उपस्थिति दर्ज करवाते हुए खुद अपनी शुरू की हुई योजना पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। चूंकि इस योजना को लेकर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन उनके ही कालखंड में हुआ था। प्रशासनिक जिम्मेदारी में राज्य सरकार की बड़ी भूमिका है।

इससे तय हो जाता है कि यह केन्द्र व राज्य सरकारों की तालमेल के साथ ही इतनी बड़ी योजना को अंजाम दिया जाता है। इसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत देश की सबसे अहम योजना है जिसके लिए हर रोज बेहतर होना अनिवार्य है व इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।

'विकसित भारत- जी राम जी विधेयक' से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

आर्थिकी

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री

यकीनन इस समय देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहे हैं। एक, ग्रामीण भारत में बढ़ती हुई आमदनी और बढ़ती हुई खपत के बीच गरीबी में लगातार कमी आ रही है। दो, हाल ही में 16 दिसंबर को सरकार के द्वारा संसद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को रद्द करने और इसकी जगह 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी वी बी जी राम जी नामक नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने संबंधी स्वीकृत किया गया विधेयक कानून बनने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हुए दिखाई देगा।

गौरतलब है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ग्रामीण भारत का योगदान बढ़ता जा रहा है। भारत ने 2024-25 में 35.77 करोड़ टन अनाज पैदा करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। पिछले दस सालों में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 10 करोड़ टन बढ़ा है। ये खेती में आत्मनिर्भरता और गांवों के विकास की तरफ देश की लगातार बढ़ती प्रतिबद्धता को दिखाता है। हाल ही में 11 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के द्वारा जारी आठवें चरण के ग्रामीण आर्थिक स्थिति एवं भावना सर्वेक्षण (आरईसीएसएस) में बताया गया है कि देश में पिछले एक साल में ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ने से खर्च करने की क्षमता और इच्छा दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। सर्वे के मुताबिक 80 फीसदी ग्रामीण परिवारों के द्वारा पिछले एक साल में अपनी खपत में वृद्धि की सूचना दी गई है। सर्वे यह भी बताता है कि निवेश और औपचारिक ऋण में भी रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है जो बढ़ती आय के समानुपातिक मानी जा सकती है। 29.3 फीसदी ग्रामीण परिवारों ने पिछले एक साल में पूंजीगत निवेश (खेती और गैर-खेती दोनों क्षेत्रों में) बढ़ाया है। केवल औपचारिक स्त्रोतों (बैंक, सहकारी संस्थाएं आदि) से कर्ज लेने वाले परिवारों का हिस्सा 58.3 फीसदी हो गया, जो सितंबर 2024 के 48.7 फीसदी था। वस्तुतः ग्रामीण भारत में बढ़ती क्रयशक्ति, वास्तविक आय वृद्धि, जीएसटी सुधार, कम महंगाई और मजबूत सरकारी समर्थन का संयुक्त परिणाम है। गाँवों में भविष्य की आर्थिक स्थिति को लेकर विश्वास बढ़ने, ग्रामीण गरीबी में कमी, छोटे किसानों की साहूकारी कर्ज की निर्भरता में कमी, ग्रामीण खपत में वृद्धि, किसानों का जीवन स्तर

> **केंद्र सरकार को गांवों में साहूकारों और अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता घटाने के लिए बैंक शाखा विस्तार के अलावा नई रणनीति के तहत दूसरे कदम उठाने की भी जरूरत है।**

बढ़ने जैसी विभिन्न अनुकूलताओं से ग्रामीण भारत मजबूती की राह पर आगे बढ़ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) रिसर्च के द्वारा गरीबी पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी में कमी शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक तेजी से हुई है। जहाँ वर्ष 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 25.7 प्रतिशत और शहरी गरीबी 13.7 प्रतिशत थी, वहीं वर्ष 2023-24 में ग्रामीण गरीबी घटकर 4.86 प्रतिशत और शहरी गरीबी घटकर 4.09 प्रतिशत पर आ गई है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि वर्ष 2019 से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय मजबूती देते हुए दिखाई दे रही है। देश के गाँवों में अप्रैल 2020 से शुरु की गई पीएम स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी जमीन का कानूनी हक देकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। अब संसद में स्वीकृत किए गए वी बी जी राम जी विधेयक के कानून बनने के बाद ग्रामीण रोजगार योजना में बड़ा बदलाव आएगा। प्रत्येक परिवार के लिए रोजगार गारंटी कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 125 करने और मौजूदा फंडिंग संरचना को बदलने का प्रस्ताव है। केंद्र और राज्यों के बीच फंडिंग की हिस्सेदारी मौजूदा अधिकतम 90:10 अनुपात के मुकाबले 60:40 के अनुपात में होगी। मसौदा विधेयक में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्य कर रही मनरेगा को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना में बदल दिया गया है। ग्रामीण रोजगार स्वाभाविक रूप से स्थानीय है और राज्यों को अब लागत और जिम्मेदारी साझा करनी होगी। जीराम जी के कानून बनने के बाद भी हमें ग्रामीण भारत के विकास और किसानों की प्रगति के लिए कई बातों पर ध्यान देना होगा। गाँवों में साहूकारों और अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता घटाने के लिए बैंक शाखा विस्तार के अलावा नई रणनीति के तहत दूसरे कदम उठाने की जरूरत है। सरकार ने किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए जो कानून बनाए हैं, उन कानूनों के पर्याप्त परिपालन पर ध्यान देना होगा।

ग्रामीण ऋण लागत कम करने और विश्वास बढ़ाने के लिए तकनीक का लाभ उठाया जाना होगा। औपचारिक ऋणों के लिए बेहतर प्रोत्साहन और डिजिटल उपकरणों से लैस बैंक प्रतिनिधियों को ग्रामीण परिवारों और संस्थानों के बीच समन्वय का माध्यम बनाया जाना होगा। नए दौर की कौशल युक्त शिक्षा तथा ग्रामीण बेरोजगारी जैसी चुनौतियों के निराकरण के लिए अधिक रणनीतिक प्रयास किए जाने होंगे। उम्मीद करें कि सरकार ग्रामीण भारत में बढ़ती हुई आमदनी और बढ़ती खपत के सुकूनदेह परिदृश्य के बीच मनरेगा के बदलाव के बाद जो वी बी जी राम जी कानून लाने जा रही है, उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकेगी और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी ।

खबर संक्षेप

बंगाल में सिंगर पर हमले की कोशिश

पूर्वी मिदनापुर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एक इवेंट के दौरान सिंगर लग्नजिता चक्रवर्ती पर शख्स ने हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। महबूब मलिक नामक शख्स पर आरोप लगाया गया है कि वह कार्यक्रम के दौरान चक्रवर्ती से कह रहा था कि जागो मां गाना बहुत हो गया, अब सेक्युलर गाना गाओ।

हरियाणा में आया भूकंप रोहतक था इसका केंद्र

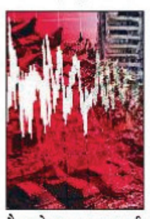

रोहतक। दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा में रविवार को भी भूकंप आया है। इससे हरियाणा के कुछ हिस्सों की धरती हिल उठी है। रविवार को हरियाणा में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.3 दर्ज की गई है। ये भूकंप दोपहर 12 बजकर 13 मिनट पर महसूस किया गया। इसका केंद्र रोहतक में धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में था।

बिजली बिल वसूलने गई टीम पर जानलेवा हमला

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बिजली बिल वसूली के दौरान बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया। मामला पैलानी थाना क्षेत्र के पिपरोदर गांव का है, जहां बकायेदार के घर बिल वसूलने गई टीम को लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है।

चुनावी बॉन्ड बंद होते ही इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए बरसे करोड़ों रुपए

भारतीय जनता पार्टी को 3,112 करोड़ तो कांग्रेस को महज 299 करोड़ रुपये मिले

2024-2025 में 9 इलेक्टोरल ट्रस्टों ने राजनीतिक दलों को कुल 3,811 करोड़ दान किए

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड के जरिए सरकार की गुमनाम राजनीतिक फंडिंग योजना को समाप्त किए जाने के बाद, पहले वित्तीय वर्ष (2024-2025) में नौ इलेक्टोरल ट्रस्टों ने राजनीतिक दलों को कुल 3,811 करोड़ रुपए दान किए। इसमें केंद्र की सत्ताधारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को 3,112 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो ट्रस्टों द्वारा दिए गए कुल फंड के 82 प्रतिशत (चार-पांचवें हिस्से) से भी अधिक है।भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को विभिन्न ट्रस्टों द्वारा सौंपी गई 'कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट' के अनुसार कांग्रेस को कुल दान का लगभग 8 प्रतिशत यानी 299 करोड़ रुपए मिले। शेष सभी दलों को मिलाकर बचा हुआ 10 प्रतिशत या लगभग 400 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। हालांकि, राजनीतिक दलों को मिलने वाला कुल दान इससे कहीं अधिक है, क्योंकि इलेक्टोरल ट्रस्ट फंडिंग का केवल एक माध्यम है, भले ही यह एक बड़ा जरिया हो।

इलेक्टोरल बॉन्ड फाइल फोटो

20 दिसंबर तक आंकड़े उपलब्ध

20 दिसंबर तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में पंजीकृत 19 इलेक्टोरल ट्रस्टों में से 13 की रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास उपलब्ध थी। इनमें से नौ ट्रस्टों ने कुल 3,811 करोड़ रुपये के योगदान की घोषणा की है। यह वित्तीय वर्ष 2023-2024 में ट्रस्टों द्वारा दिए गए 1,218 करोड़ रुपये के मुकाबले 200% से भी अधिक की वृद्धि है। वहीं, चार ट्रस्टों (जनहित, परिवर्तन, जयहिंद और जयभारत) ने इस वर्ष कोई योगदान नहीं देने की घोषणा की है।

प्रूडेंट और प्रोग्रेसिव ट्रस्ट का दबदबा

'प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट' भाजपा को चंदा देने वाला प्रमुख डोनर बनकर उभरा है, जिसने 2,180.07 करोड़ दिए। इस ट्रस्ट को मुख्य रूप से जिंदल स्टील एंड पावर, मेघा इंजीनियरिंग, भारती एयरटेल, ऑरोबिंदो फार्मा और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनियों से फंड मिला था। प्रूडेंट ने कांग्रेस, टीएमसी, आप और टीडीपी को भी दान दिया, लेकिन 2,668 करोड़ के फंड का लगभग 82 प्रतिशत हिस्सा भाजपा को गया।

सभी पार्टियों को मिला चंदा

प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने कांग्रेस, टीएमसी, आप , टीडीपी और दूसरी पार्टियों को डोनेशन दिया, लेकिन 2024-2025 में उसके कुल 2,668 करोड़ रुपए के डोनेशन का बड़ा हिस्सा भाजपा को गया। इसी तरह, 'प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट' ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न कंपनियों से 917 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें से 914.97 करोड़ रुपए दान किए गए। इस राशि भाजपा के खाते में गया। इस ट्रस्ट में मुख्य योगदान टाटा समूह की कंपनियों जैसे टाटा संस, टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा पावर का रहा।

अन्य ट्रस्टों का योगदान

मुंबई स्थित केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, 'जनप्रगति इलेक्टोरल ट्रस्ट' को दान देने वाली एकमात्र फर्म रही। ट्रस्ट को मिले कुल 1.02 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए शिवसेना (यूबीटी) को दान किए गए। 'हार्मनी इलेक्टोरल ट्रस्ट' को 35.65 करोड़ रमिले, जिसमें से उसने 30.15 करोड़ भाजपा को दिए। इसमें भारत फोर्ज (22 करोड़) और कल्याणी स्टील जैसी कंपनियों का मुख्य योगदान रहा।'न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट' को महिंद्रा समूह की कंपनियों से कुल 160 करोड़ भाजपा को दिए गए। 'ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट' को मिले 25 करोड़ में से 21 करोड़ भाजपा को मिले, जिसमें सीजी पावर का सर्वाधिक योगदान था। वहीं, 'जनकल्याण ट्रस्ट' को मिले कुल 19 लाख को भाजपा और कांग्रेस के बीच बराबर (9.5 लाख प्रत्येक) बांट दिया गया।

पिछले वर्ष भी भाजपा थी मालामाल

उल्लेखनीय है कि पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) में भाजपा को कुल 3,967.14 करोड़ रुपए का स्वैच्छिक योगदान मिला था, जिसमें 43 प्रतिशत हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड का था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद, अब कंपनियां चेक, डीडी या यूपीआई ट्रांसफर के जरिए सीधे या इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से दान करती हैं, जिसकी जानकारी चुनाव आयोग को देना अनिवार्य है।

जीत की खुशी व्यक्त करते भाजपा कार्यकर्ता

महाराष्ट्र में नपं और नप चुनाव

महायुति को 288 में से 218 सीटें, एमवीए 47 पर रुकी

मुंबई। महाराष्ट्र में नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों के सभी 288 में से 288 नतीजे या रुझान सामने आ चुके हैं। इनमें महायुति गठबंधन ने स्पष्ट बढ़त हासिल की है, जबकि महाविकास आघाड़ी को बेहद कम सीटों पर संतोष करना पड़ा है। भाजपा ने 127 सीटें जीतकर महायुति में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खुद को स्थापित किया है। वहीं शिवसेना को 54 सीटें और एनसीपी को 37 सीटें मिली हैं। इस तरह महायुति के खाते में 218 सीटें गई हैं, जो गठबंधन की मजबूत को दर्शाता है। दूसरी ओर एमवीए का प्रदर्शन सीमित रहा है। कांग्रेस ने 31 सीटें जीतकर आघाड़ी में सबसे आगे रहने का दावा किया है।

भाजपा फिर नंबर वनः फडणवीस

भाजपा की इस जीत पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के मार्गदर्शन में और सभी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से भाजपा एक बार फिर राज्य में नंबर 1 है। सभी को बधाई।

एमवीए के बराबर तो शिवसेना की ही सीटें

एकनाथ शिंदे ने कहा कि एमवीए ने जितनी सीटें जीती हैं उससे ज्यादा तो अकेले शिवसेना ने जीत ली हैं। कुछ लोग शिवसेना सिर्फ ठाणे तक ही सीमित समझते हैं, लेकिन अब चुनाव परिणाम ने दिखा दिया है कि ऐसा नहीं है। शिवसेना का प्रभाव बाहर भी है।

भगवान अयप्पा की 'पालकी'

हैदराबाद। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी अपने बेटे के साथ रविवार को हैदराबाद के हिमायत नगर में 'पड़ी पूजा' समारोह के दौरान भगवान अयप्पा की 'पालकी' ले जाते हुए।

अरावली की पहाड़ियां फिर चर्चा में

खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मची हलचल, इस पर सियासत भी गरमाने लगी

'सेव अरावली कैंपेन' भी चल पड़ा

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

अरावली के पर्वत दुनिया में सबसे प्राचीन पर्वत

अरावली के

अरावली के पर्वत दुनिया में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं। इनसे जुड़ा एक ताजा मामला सोशल मीडिया पर अभियान का रूप ले रहा है।इन पर्वतों के पास खनन की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित है। इस पर केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जवाब दाखिल किया। इसके बाद से कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, जिन्हें लेकर यह श्रृंखला चर्चा के केंद्र में आ गई। अरावली के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 'सेव अरावली कैंपेन' अभियान तक चल पड़ा है।

अरावली के पर्वत दुनिया में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल

अरावली की पहाड़ी

अरावली पर्वत श्रृंखला की महत्ता

पृथ्वी पर अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह करीब दो अरब साल पुरानी है। यह हिंद-गंगीय मैदानी इलाकों को रेगिस्तानी रेत से बचाने के लिए एक अहम पारिस्थितिकी बैरियर की तरह काम करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यह पर्वत श्रृंखला न होती तो भारत का उत्तरी क्षेत्र रेगिस्तान में तब्दील होना शुरू हो गया होता।

अरावली बचेगी तो ही दिल्ली-एनसीआर भी बचेगा

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्लीवासियों को अरावली पहाड़ियों को बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं बल्कि संकल्प होना चाहिए। एक्स पर एक लंबे संदेश में उन्होंने कहा कि बची रहे जो 'अरावली' तो दिल्ली रहे हरीभरी!

बाइक से गिरकर तीन युवक गंभीर घायलः कोन-खरौंधी मार्ग पर हादसा, जिला अस्पताल रेफर

कोन (सोनभद्र), कोन-खरौंधी मार्ग पर शनिवार दोपहर एक बाइक दुर्घटना में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा खरौंधी गांव के पास हुआ, जिसमें घायलों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल लोढ़ी रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, घघिया निवासी पप्पू गुप्ता (पुत्र शिवकुमार गुप्ता), कोन निवासी अभिषेक गुप्ता (पुत्र अरविंद गुप्ता) और दीनानाथ भारती (पुत्र राजाराम भारती) एक ही बाइक से किसी काम से जा रहे थे। खरौंधी के समीप उनकी बाइक अचानक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तत्काल परिजनों और एंबुलेंस को सूचना दी।

मृतक से लेकर दुकानदार तक को फर्जी हाजिरी पर मनरेगा भुगतान

महराजगंज जनपद के परतावल विकास खंड की ग्राम पंचायत महम्मदा में मनरेगा योजना के तहत फजीवाड़े का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, यहां मृतक, बुजुर्ग, दिव्यांग, दुकानदार, वाहन चालक और बाहर काम करने वाले लोगों के नाम पर भी मनरेगा मजदूरी भुगतान कराकर सरकारी धन की अवैध वसूली की जा रही है। ग्रामीण विक्रम, विश्राम, चन्द्रशेखर, पारसनाथ, रामा, सुनील, रामप्रताप सहित अन्य लोगों ने उच्चाधिकारियों से शिकायत कर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकताओं का कहना है कि गांव के विक्रम की मृत्यु हो चुकी है, इसके बावजूद 24 मई 2025 से 8 जून 2025 तक उनके नाम से मनरेगा कार्यों में हाजिरी लगाकर भुगतान कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि नथुनी, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और कभी मनरेगा में काम ही नहीं किया, उनके खाते में भी मजदूरी की राशि भेजी गई। इसी तरह 80 वर्षीय बुजुर्ग शिवचरण, ट्रक चालक सुरेंद्र, बाजार में सब्जी बेचने वाले राकेश, परतावल में कार्यरत धर्मेन्द्र के नाम पर भी भुगतान दशार्या गया।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०-/ब-121/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक वसुन्धरा न्यू सिल्वर इन्क्लेव द्वारा भागीदार मो० इरशाद खान आ० स्व०अब्दुल हकीम खान निवासी दत्ता कॉलोनी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित खसरा नंबर 4442/1 रकबा 0.251 हे0 भूमि में से रकबा 111-63 वर्गमीटर भूमि भूमि को अनावेदक क्रमांक-1 इमतियाज अंसारी आ० नेयाज अहमद के पास अंकन राषि रुपए 6,40,000/-, खसरा नंबर 4442/1 रकबा 0.251 हे0 भूमि में से रकबा 111-63 वर्गमीटर भूमि भूमि को अनावेदक क्रमांक-2 सुफियान अहमद आ०नेयाज अहमद के पास अंकन राषि रुपए 6,40,000/-, खसरा नंबर 4442/1 रकबा 0.251 हे0 भूमि में से रकबा 113-50 वर्गमीटर भूमि को अनावेदक क्रमांक-3 रिजवान अहमद आ० नेयाज अहमद के पास अंकन राषि रुपये 6,45,000/-, खसरा नंबर 4450/1 रकबा 0.126 है0 भूमि में से रकबा 112-50 वर्गमीटर भूमि को अनावेदक क्रमांक-4 जेबा नसरीन पति मो० नसीम अंसारी के पास अंकन राषि रुपये 6,40,000/-, खसरा नंबर 4450/1 रकबा 0.126 हे0 भूमि में से रकबा 219.60 वर्गमीटर भूमि को अनावेदक क्रमांक-5 रेयाज अहमद अंसारी आ० नेयाज अहमद के पास अंकन राषि रुपए 12,50,000/- में बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एंव प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 07/01/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः 15/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०-/ब-121/2025-26
ईश्तहार

एत्तद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कृष्णानंद सिंह आ०स्व० आर०बी० सिंह पार्टनर वसुंधरा बिल्डर्स निवासी नगर पालिका निगम के पास केदारपुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०म० के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित खसरा नंबर 4450/2, 4451/1 रकबा 0-012, 0.202 हे0 भूमि में से रकबा 25.03. 174.9 वर्गमीटर कुल 199.95 वर्गमीटर भूमि को अनावेदक क्रमांक। सुफियाना अहमद आग्नेयाज अहमद के पास अंकन राशि रुपए 11,40,000/- खसरा नंबर 4450/2, 4451/1 रकबा 0.012, 0.202 हे0 मेसे 12.80, 80 वर्गमीटर कुल 92.80 वर्गमीटर को अनावेदक क्रमांक-2 फरहत जहां पति रियाज अहमद के पास अंकन राशि रुपये 5,30,000/- खसरा नंबर 4450/2, 4551/1 रकबा 0.012, 0.202 हे० मेसे 12.44.76 वर्गमीटर कुल 88.44 वर्गमीटर को फरीजा जर्बी पिता रियाज अहमद के पास अंकन राशि रुपए 5,05,000/- में बोध एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो पत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 07/01/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से स न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः - 19/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर, सरगुजा

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०/ब-121/2025-26
//ईश्तहार//

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक देव्यांशु सिंह आ० स्व० देवेन्द्र कुमार सिंह, व अन्य 02, निवासी विजय मार्ग संगम चौक अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा छ०ग० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा०) अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदकगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम असोला स्थित भूमि खसरा नंबर 553/6 रकबा 0.252 हे0 में से रकबा 0.132 हे0 विक्रय किया गया है, वर्तमान में उक्त भूमि का रकबा 0.120 हे0 होना चाहिए किन्तु त्रुटिवश रकबा 0.020 हे० अंकित है। इसी प्रकार खसरा नंबर 554/2 रकबा 0.338 हे0 में से रकबा 0.163 हे० विक्रय किया गया है, विक्रय उपरांत रकबा 0.175 शेष होना चाहिए था, किन्तु त्रुटिवश रकबा 0.127 हे0 अंकित है। आवेदकगण द्वारा उक्त त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। जो जांच व प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 12/01/2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 15/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-02

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०-/ब-121/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक तुलिका सिंह पत्नी सम्पूर्णानन्द 'सिंह निवासी रामनिवास नगर नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित खसरा नंबर 253/23 रकबा 0.012 हे० भूमि को अनावेदक उमेश कुमार पाण्डेय आ०राजमणि पाण्डेय निवासी नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास अंकन राषि रुपये 40,00,000/- में बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एंव प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 07/01/2026 के पूर्व स्वयं प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांकः- 15/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर, सरगुजा

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष
ग्राम - प.ह.न. 13
ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुकला देवी पति चन्द्रशेखर प्रसाद जाति कुम्हार निवासी ग्राम भैयाथान प.ह.न.13. रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान, जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक स्वयं सुकला देवी आ० गणेश का जन्म दिनांक 01/01/1955 को ग्राम भैयाथान मैं हुई है, अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक स्वयं सुकला देवी जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत भैयाथान को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ये स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 29/12/2025 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 12/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भैयाथान जिला - सूरजपुर (छ०ग०)

न्यायालय तहसीलदार/कार्यपालिक दंडाधिकारी रामानुजनगर जिला सूरजपुर (छग)
// ईस्तहार //
रा०प्र०क्र० इ/12/25-26

आम जनता ग्रामवासी ग्राम सेंदुरी को सूचित किया जाता है कि सुशीला आत्मज मुन्ना राम जाति गोंड़ ग्राम सेंदुरी थाना रामानुजनगर तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर(छ ग)?द्वारा अपने पिता मुन्ना राम आत्मज सुमार साय का मृत्यु दिनांक 25/01/2021पच्चीस जनवरी दो हजार एक्कीस के हो जाने से पिता मुन्ना राम आत्मज सुमार साय का मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जिस किसी आम जनता/ ग्रामवासीयों को कोई आपत्ति/आक्षेप तो वह अपना आपत्ति दिनांक 02/01/25 को इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है , नियत तिथि के पस्चात कोई विचार नहीं किया जाएगा और कार्रवाई कर दी जाएगी।

दिनांक 20/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया है।

तहसीलदार/कार्यपालिक दंडाधिकारी
रामानुजनगर जिला सूरजपुर (छग)

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क्र./ब/121 वर्ष
ग्राम प.ह.न.
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जगलराम पिता सुकुल राम जाति कवर निवासी ग्राम मोहली प.ह.न. रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के भाई दिलेश्वर का जन्म दिनांक 20-11-2009 को ग्राम मोहली में हुई है. अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने पुत्र भाई दिलेश्वर का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत मोहली को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में 'जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ये स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 24/12/25 आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 08/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

तहसीलदार तहसील
भैयाथान जिला सूरजपुर

प्रोजेक्ट संकल्प आश्रम-छात्रावासों के बच्चों का संवर रहा भविष्य : प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा प्रदेश में प्रारंभ किए गए ह्यप्रोजेक्ट संकल्पह्व के माध्यम से आश्रम छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रहे बच्चों का भविष्य संवर रहा है। विभाग की इस नई पहल से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक के साथ नैतिक, सामाजिक एवं जीवन कौशल से भी सशक्त बनाया जा रहा है। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश एवं विभागीय मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में छात्रावासी बच्चों के भविष्य को नई उड़ान देने के उद्देश्य से यह अभिनव पहल की गई है।

छोटा बीज बड़े वृक्ष का बनता है आधार

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि जिस प्रकार छोटा बीज बड़े वृक्ष का आधार बनता है उसी प्रकार एक छोटी सकारात्मक पहल समाज में क्रांति ला सकती है। यदि विद्यार्थी को प्रारंभ से ही उच्च आदर्शों पर आधारित शिक्षा प्राप्त होगी तो वह आगे चलकर समाज एवं राष्ट्र में अपना सकारात्मक योगदान देने में सक्षम होगा। प्रोजेक्ट संकल्प इसी कड़ी में ह्यह्यएक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि इस पहल के अंतर्गत छात्रावासों में अध्ययनरत बच्चों के शैक्षणिक अध्ययन के साथ-साथ रचनात्मक गतिविधियों, अनुशासन, जीवन कौशल एवं व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छात्र-छात्राओं को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण भोजन, नियमित शैक्षणिक सहयोग तथा खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें हैदराबाद के सुप्रसिद्ध प्रेरक वक्ता नंदा द्वारा निस्वार्थ भाव से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण सत्र के दौरान नंदा ने छात्रावास अधीक्षकों को छात्रावास-आश्रमों में सकारात्मक

सोच विकसित करने के सामान्य, परंतु प्रभावी तरीके बताएं। उन्होंने बच्चों को अनुशासन में रखने, उनमें अच्छी आदतें विकसित करने, अपने कार्य पर पूर्ण फोकस करने, समय का महत्व समझने, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने, नियमित व्यायाम करने, स्वयं भी खुश रहने एवं अपने सहपाठियों को भी खुश रखने तथा सबके साथ अच्छे मधुर संबंध बनाने के गुर बताएं।

छोटी सकारात्मक पहल बच्चों के जीवन में ला सकती है बड़ा परिवर्तन

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि प्रोजेक्ट संकल्प के प्रथम चरण के अंतर्गत 16 से 18 अक्टूबर 2025 को रायपुर में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के साथ एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। छात्रावास-आश्रमों से जुड़ी सामान्य एवं व्यवहारिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई एवं उनके सकारात्मक सरल एवं प्रभावी निदान नंदा द्वारा बताए गए। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के मानसिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास को लेकर उपयोगी सुझाव साझा किए गए। इसी कड़ी में आज पोस्ट मैट्रिक छात्रावास-आश्रमों के अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर श्री बोरा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि एक छोटी-सी सकारात्मक पहल भी बच्चों के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। उल्लेखनीय है कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावास-आश्रमों में अध्ययनरत बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं। विभागीय मंत्री जी एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर छात्रावास-आश्रमों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाती है, ताकि बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी न रहे।

मेगा हेल्थ कैंप 2025 : निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं से आमजन को मिला बड़ा संबल: मंत्री श्रीमती राजवाड़े

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप 2025 ने जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सशक्त और संवेदनशील पहल के रूप में अपनी पहचान बनाई है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने शिविर में सहभागिता करते हुए इसकी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और नागरिकों से संवाद किया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए चिकित्सा स्टॉलों का अवलोकन किया तथा उपचार हेतु आए लोगों से बातचीत कर उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि एक ही स्थान पर निःशुल्क जांच, उपचार और विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराना शासन की जनहितकारी सोच को दर्शाता है। ऐसे शिविर विशेष रूप से गरीब, श्रमिक एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने स्वयं भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया और कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच को जीवनशैली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ी सिनेमा हमारी लोकसंस्कृति और अस्मिता का जीवंत दस्तावेज-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफरह्व कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा की विकास यात्रा, उपलब्धियों और उज्ज्वल भविष्य पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के गठन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि छालीवुड की सशक्त नींव रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने निगम के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय श्री राजेश अवस्थी का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि उनका असामयिक निधन न केवल छत्तीसगढ़ी सिनेमा, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा आज एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने निगम की वर्तमान अध्यक्ष सुश्री मोना सेन को एक अनुभवी, कर्मठ और समर्पित कलाकार बताते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में छालीवुड का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ी फिल्में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की संस्कृति, कला और पहचान को और अधिक सशक्त रूप में स्थापित करेंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1957 से प्रदेश में फिल्मों के निर्माण का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उन्होंने भूलन कांदा उपन्यास पर आधारित फिल्म भूलन द मेजह्व को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार को पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा की जड़ें लोक संस्कृति, लोककथाओं और सामाजिक सरोकारों से गहराई से जुड़ी हैं, जो इसे विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा हमारी लोकसंस्कृति और अस्मिता का जीवंत दस्तावेज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी फिल्मों के विकास को लेकर पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश में छालीवुड का भविष्य स्वर्णिम है और फिल्म उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक वर्ष प्रदेश के चहुंमुखी विकास की नई इबारत लिख रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले निमार्ताओं और वरिष्ठ कलाकारों मोहन सुंदरानी, सतीश जैन, संतोष जैन, मनोज वर्मा, अनुज शर्मा और प्रेम चंद्राकर को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन ने मुख्यमंत्री श्री साय का अभिनंदन करते हुए निगम के पुनर्गठन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छइंहा भुइंयाह्व के निमार्ता सतीश जैन को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस फिल्म ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के समग्र और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े दिव्यांग युवक-युवती परिचय सम्मेलन में हुई शामिल

विकलांग नहीं, दिव्यांगजन कहकर करें संबोधन-श्रीमती राजवाड़े

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा का अभिन्न अंग हैं और उनके प्रति संवेदनशील सोच व सम्मानजनक भाषा का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। वे अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद (छत्तीसगढ़ प्रांत) के तत्वावधान में आशीर्वाद भवन, बैरन बाजार, रायपुर में आयोजित 16वें राज्य स्तरीय विवाह योग्य युवक-युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े दिव्यांग युवक-युवती परिचय सम्मेलन में हुई शामिल मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े

दिव्यांग युवक-युवती परिचय सम्मेलन में हुई शामिल मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े दिव्यांग युवक-युवती परिचय सम्मेलन में हुई शामिल मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने अपने संबोधन में कहा कि यह सम्मेलन केवल परिचय का मंच नहीं, बल्कि दिव्यांग युवक-युवतियों को गरिमापूर्ण वैवाहिक जीवन की ओर अग्रसर करने का सार्थक प्रयास है। उन्होंने जानकारी दी कि सम्मेलन में सहमति बनने वाले जोड़ों का सामूहिक विवाह 28 फरवरी 2026 एवं 01 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सम्मेलन की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि इसमें सामान्य युवक-युवतियाँ भी शामिल हुए, जो दिव्यांगजनों से विवाह के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे आए। यह सामाजिक समावेशन और समानता की दिशा में प्रेरक पहल है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कार्यक्रम के दौरान एक महत्वपूर्ण सामाजिक अपील करते हुए कहा कि विकलांगह्व के स्थान पर दिव्यांगजनह्व शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान और आत्मबल को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दिव्यांगजनह्व शब्द के प्रयोग का आग्रह किया है। शब्द हमारी सोच और संवेदना को दशार्ते हैं, इसलिए समाज को सम्मानजनक भाषा अपनानी चाहिए। कार्यक्रम में विधायक माननीय पुरंदर मिश्रा, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ. विनय पाठक, चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. विनोद पाण्डेय, अग्रवाल समाज अध्यक्ष विजय अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक विरेंद्र पाण्डेय, राजेश अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक, बड़ी संख्या में दिव्यांगजन एवं उनके परिजन उपस्थित रहे। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार दिव्यांगजनों के अधिकार, सम्मान और सामाजिक समावेशन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक परिवर्तन की मजबूत नींव रखते हैं।

बरसात में उफनते नदी-नाले अब नहीं रोकेंगे ग्रामीणों का रास्ता : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी करोड़ों की सौगात

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। 130 करोड़ की लागत से जशपुर जिले में बनेंगे 237 पुल-पुलिया जशपुर जिले में बरसात के दिनों में ग्रामीणों के आवागन की बाधा को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर 237 पुल-पुलियों के निर्माण के लिए 130 करोड़ रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत हुई है, जिससे नदियों पर उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के साथ ही नालों पर पुल-पुलिया का तेजी से निर्माण कराया जा रहा है, इससे विकास को नई गति मिलेगी। बरसात के दिनों में उफनते नदी-नाले अब ग्रामीणों का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव

साय ने जशपुर जिले में 22 उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण के लिए 109 करोड़ 09 लाख रुपये की मंजूरी दी है। ये पुल जिले के प्रमुख मार्गों और नदियों-नालों पर बनाए जा रहे हैं, जिससे वर्षभर निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही गांव-टोला और पारा को जोड़ने के उद्देश्य से 215 छोटे पुल-पुलिया निर्माण हेतु 20 करोड़ 93 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। गौरतलब है कि जशपुर जिले में बरसात के दिनों में कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट जाता था, जिससे किसानों, छात्रों, मरीजों और आम नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पुल-पुलिया निर्माण से न केवल आवागमन सुरक्षित होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और कृषि गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी।

पत्रकारों की लेखनी केवल सूचना का माध्यम ही नहीं, पर्यटन को प्रोत्साहन देने का एक सशक्त साधन भी - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजस्थान के अंतर्राज्यीय अध्ययन भ्रमण से लौटे पत्रकारों के दल ने की सौजन्य मुलाकात

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजस्थान के अंतर्राज्यीय अध्ययन भ्रमण से लौटने के उपरांत छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के दल ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर पत्रकारों ने 15 से 20 दिसम्बर तक राजस्थान भ्रमण के दौरान वहां की विधायिका, प्रशासनिक कार्यप्रणाली तथा पर्यटन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के अनुभवों को साझा किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए अंतर्राज्यीय अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, ताकि अन्य राज्यों के शासन-प्रशासन, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास से जुड़े नवाचारी प्रयासों को पत्रकारों के दृष्टिकोण से समझा जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे अध्ययन भ्रमणों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर छत्तीसगढ़ में भी नई और प्रभावी पहल शुरू की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे इस यात्रा के अनुभवों को यात्रा-वृत्तांत के रूप में लिपिबद्ध करें, जिससे यह आम पर्यटकों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की लेखनी केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने का एक सशक्त साधन भी है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बस्तर धरती पर स्वर्ग के समान है, किंतु नक्सलवाद लंबे समय तक इसके विकास में एक बड़ी बाधा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के अनुरूप मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ

कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पर्यटन को राज्य की नई उद्योग नीति में शामिल किया गया है। इसके तहत सुदूर वनांचलों में होम-स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पर्यटक ग्रामीण परिवारों के साथ रहकर उनकी संस्कृति, खान-पान और जीवनशैली को नजदीक से अनुभव कर सकें। इससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि विश्व के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों में छत्तीसगढ़ के धुड़मारास को शामिल किया जाना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि इन पर गंभीरता से विचार कर उन्हें अमल में लाया जाएगा। इस अवसर पर जशपुर से विजय त्रिपाठी ने बताया कि राजस्थान भ्रमण के दौरान वहां की विधानसभा देखने का अवसर मिला, जहां आमजन को विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधानसभा की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए एक भव्य संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इस संग्रहालय के माध्यम से राज्य निर्माण से लेकर वर्तमान तक की विधायी यात्रा और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के योगदान को समझने का अवसर मिलता है। कोरबा से विजय खेत्रपाल ने कहा कि इस अध्ययन भ्रमण के माध्यम से यह समझने का अवसर मिला कि राजस्थान में सैकड़ों वर्ष पुराने किलों और महलों को आधुनिक जनसुविधाओं से जोड़कर पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया गया है। इसके साथ ही रेगिस्तानी क्षेत्रों में जीप सफारी, ऊंट सवारी, पैरा-सेलिंग, डेजर्ट कैंप जैसी गतिविधियों के माध्यम से पर्यटन को आकर्षक रूप दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रभावी केस स्टडी हो सकती है। जगदलपुर के अर्जुन झा ने जयपुर स्थित चोकरधानी के अनुभव साझा करते हुए कहा कि वहां ग्रामीण जीवन, लोकसंस्कृति और खान-पान को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसी प्रकार बस्तर पंडुम के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति को पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। श्री टिंकेश्वर तिवारी ने भी राजस्थानी खान-पान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों को पर्यटन स्थलों पर प्रमुखता से बढ़ावा देने पर जोर दिया। स्टेट न्यूज सर्विस के युवा पत्रकार रजत अवस्थी ने राजस्थानी टोपी साफा से मुख्यमंत्री श्री साय का सम्मान करते हुए पत्रकार भ्रमण योजना को प्रारम्भ करने के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी आलोक सिंह, जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक संजीव तिवारी, संयुक्त संचालक जितेंद्र नागेश सहित पत्रकारगण एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन कर केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी

कांग्रेसी बोले--केन्द्र सरकार मनरेगा की हत्या कर गरीबों के काम का अधिकार छिनने कर रही कार्य

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। केन्द्र सरकार के द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर नए कानून लाने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहां अग्रसेन चौक पर हल्ला बोल धरना प्रदर्शन कर केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। मनरेगा की हत्या बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गरीबों के काम का अधिकार छिनने का कार्य केन्द्र सरकार कर रही है और सुधार के नाम पर योजना बंद करना चाह रही है। गरीब तबके के संवैधानिक अधिकार छिनने की साजिश और करोड़ो मजदूरों को योजना से बाहर करने का आरोप लगाते हुए दो दशकों से करोड़ो परिवार की जीवन रेखा मनरेगा को लेकर केन्द्र सरकार की खिलाफत करते हुए तीखा हमला किया और कहा कि गरीबो से काम का अधिकार छिन लिया है। मनरेगा के बदलावों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेताओं व जनप्रतिनिधियों ने बताया कि

लोकसभा में विधेयक पारित कर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना को धीरे-धीरे खत्म करने का रास्ता साफ कर लिया है। कांग्रेसियों का आरोप था कि पीएम मोदी मनरेगा के विरोधी रहे हैं और बीते पांच वर्षों में मनरेगा के 100 दिन की गारंटी महज 50 से 55 दिन पर आकर टिक गई है। इसके पूर्व स्थानीय अग्रसेन चौक में बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस नेताओं ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह के नेतृत्व में हुंकार भरते हुए धरना प्रदर्शनन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष शशि सिंह सहित इस्माईल खान, सुनील अग्रवाल, विमलेशदत्त तिवारी, अनिल गुप्ता, जगत आयाम, बिहारी कुलदीप, आनंद कुंवर, विमला सिंह, गोपाल शर्मा, गोवर्धन सिंह, संतोष पावले, अभिषेक शर्मा सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान कटघोरा के पास हुई हृदय विदारक घटना में सूरजपुर के एक ही परिवार से तीन सदस्यों के निधन व कांग्रेस परिवार के साथी व उनके परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का संचालन शहर कांग्रेस अध्यक्ष संजय डोसी ने किया। कार्यक्रम के दौरान हेमलता राजवाड़े, नवीन जायसवाल, प्रवेश गोयल, पवन साहू, संजीव श्रीवास्तव, जगत आयाम, दिनेश गुप्ता, परमेश्वर राजवाड़े, विक्की समद्दार, मासूम ईराकी, कमलेश राजवाड़े, अनूप गुप्ता, दिव्या तांजे, विकास सिंह, वेद प्रकाश मिश्रा, चंदुल कुशवाहा, तपन सिकदार, जमील सिद्दीकी, सुनील सारथी, समीर सिंह, शक्ति ठाकुर, शांतु डोसी, संजीत यादव, रहमान खान, संजीव सेट्टी, चन्द्रदत्त दुबे, आशीष सिंह, राम कुमार देवांगन, अभय कुमार, भावना सिंह, मेदनी सिंह, राजू गुप्ता, बुधराम राजवाड़े, जरीना सुलताना, राजेश साहू, भोले साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस व अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रशासन की टीम ने 222 बोरी अवैध धान किया जप्त

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को इमलीपारा भटगांव से सिरसी समिति की ओर अवैध रूप से 170 बोरी लगभग 70 क्विंटल धान का परिवहन किया जा रहा था। जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित व्यक्ति के पास दूसरे तहसील से भैयाथान तहसील में धान परिवहन किए जाने संबंधी कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। प्रशासनिक अमले द्वारा उक्त धान को जोड़ा सरई के पास पकड़कर नियमानुसार कार्रवाई की गई तथा धान को समिति सिरसी के सुपुर्दगी में सौंपा गया। दूसरी कार्रवाई में ग्राम कसलगिरि के पास अवैध रूप से धान का परिवहन करते हुए एक पिकअप वाहन को पकड़ा गया। जांच के दौरान पिकअप में 52 बोरी अवैध धान पाया गया। मौके पर ही धान एवं वाहन को जप्त कर सुपुर्दगी में लेकर चौकी लटोरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पशु तस्करी में जप्त 1 वाहन को राजसात करने कलेक्टर ने जारी किया आदेश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। पशु तस्करी में जब्त किए गए एक वाहन को शासन के पक्ष में राजसात करने का आदेश कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट एस जयवर्धन ने जारी किया है। इस मामले में राजसात की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन एसएसपी प्रशांत ठाकुर ने कलेक्टर को भेजा था।

राजसात किए गए वाहन में 30 जनवरी 2024 की रात्रि में वाहन चालक मालिक अरबाज अली पिता असगर अली उम्र 20 वर्ष ग्राम गुमला, हुसैननगर थाना व जिला गुमला झारखण्ड के द्वारा कृषि योग्य पशुओं को क्रूरतापूर्वक महेन्द्रा बोलेरो पिकअप वाहन में ठूस-ठूसकर भरकर रस्सी से बांधकर दिगर राज्य झारखण्ड ले जाते समय वाहन चालक द्वारा पिकअप को गड्ढा में धकेल दिया। जिससे 3 मवेशी की मृत्यु हो गई शेष 7 मवेशी रात में ही जंगल की ओर चले गए, मृत मवेशियों का पीएम कराया गया। इस मामले प्रेमनगर वाहन मालिक चालक अरबाज अली को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इस मामले में कलेक्टर ने विधिवत् सुनवाई पूरी करते हुए पिकअप

पुलिस ने कार्यवाही करते हुए धारा 429 भादवि, छ.ग. कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(घ) के तहत मामला पंजीबद्ध कर बिना नंबर महेन्द्र बोलेरो पिकअप वाहन को जप्त कर वाहन के राजसात का आदेश जारी किया है। अब इस वाहन की नीलामी कर प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में जमा कराई जाएगी। यदि न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त होता है, तो आगे की कार्रवाई उसी के अनुरूप की जाएगी।

एसआईआर के तहत फॉर्म-6 कलेक्शन कार्य का एसडीएम ने किया निरीक्षण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। एसआईआर के अंतर्गत मतदाता सूची के अद्यतन कार्य को जिले में प्रभावी ढंग से संपादित किया जा रहा है। इसी क्रम में एसडीएम प्रतापपुर ललिता भगत द्वारा फॉर्म-6 कलेक्शन हेतु बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्य का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान ग्राम स्तर पर नए मतदाताओं को फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों तथा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही बीएलओ को समयबद्ध एवं त्रुटिरहित कार्य करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा भी अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर बीएलओ द्वारा किए जा रहे फॉर्म-6 कलेक्शन कार्य की समीक्षा की जा रही है तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देशानुसार ग्राम बंशीपुर एवं जरही में भी बीएलओ द्वारा फॉर्म-6 कलेक्शन कार्य का निरीक्षण किया गया। जिला प्रशासन ने नागरिकों, विशेषकर नए मतदाताओं से अपील की है कि वे समय पर फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना सुनिश्चित करें।

सुशासन सप्ताह, जिले के 16 सौ नवनिर्मित आवासों में कराया गया गृह प्रवेश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सुशासन सप्ताह पर राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर एस. जयवर्धन व सीईओ जिला पंचायत विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में एक नवंबर के बाद पूर्ण हुए पीएम आवास के हितग्राहियों द्वारा निर्मित आवासों में गृह प्रवेश कार्यक्रम कराया गया। उक्त तारतम्य में सोमवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विजेंद्र सिंह पाटले द्वारा जनपद पंचायत ओड़गी के ग्राम पंचायत दवना में हितग्राही प्रमिला,नंदीलाल को आवास में विधिवत पूजा

पाठ के साथ गृह प्रवेश कराया गया। इस अवसर पर अल्प समय में आवास पूर्ण करने पर हितग्राही को सम्मानित किया गया। उपस्थित अन्य हितग्राहियों को जल्द आवास पूर्ण करने के लिए समझाइश दी गई, पंपलेट एवं तकनीकी मार्गदर्शिका की प्रति वितरित किए गए। आज जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों एवं योजना के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा निर्मित आवासों का गृह प्रवेश कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसके साथ ही आवास चौपाल के माध्यम से हितग्राहियों को योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

पल्स पोलियो अभियान के प्रथम दिन जिले में 95,382 बच्चों को पिलाई गई जिंदगी की दो बूंद

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.डी. पैकरा तथा जिला टीकाकरण अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में पल्स पोलियो अभियान सफलतापूर्वक संचालित

किया जा रहा है। अभियान के तहत आज प्रथम दिन बूथों में कुल 1,04,660 लक्षित बच्चों में से 95,382 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जिससे जिले ने 91 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि शेष बचे बच्चों को घर-घर जाकर कल एवं परसों पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। उल्लेखनीय है कि प्रतापपुर ब्लॉक में 18,964 में से 17,432 बच्चों को, भैयाथान ब्लॉक में 18,084 में से 16,487 बच्चों को, ओड़गी विकासखंड में 10,955 में से 10,144 बच्चों को, प्रेमनगर विकासखंड में 8,351 में से 7,403 बच्चों को और रामानुजनगर विकासखंड में 15,165 में से 13,838 बच्चों को दवा पिलाई गई। सूरजपुर शहरी क्षेत्र में 2,430 में से 2,384 बच्चों को, सूरजपुर ग्रामीण क्षेत्र में 30,711 में से 27,694 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई।उल्लेखनीय है कि अभियान के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पल्स पोलियो टीकाकरण केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि अभियान को प्रभावी एवं सफल बनाया जा सके। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलवाएं और अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।

घने कोहरे की गिरफ्त में कोयलांचल, दोपहर की धूप से राहत

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। कोयलांचल समेत आसपास इलाकों में बीते 3-4 दिनों से सुबह का नजारा मानो किसी पहाड़ी पर्यटन स्थल जैसा नजर आ रहा है। चारों ओर पसरा घना कोहरा पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। तड़के सुबह जब लोग नींद से जागते हैं तो बाहर झांकते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा क्षेत्र सफेद चादर ओढ़कर सो रहा हो। कोहरे की मोटी परत ने न केवल दृश्यता को बेहद कम कर दिया है, बल्कि आम जनजीवन की रफ्तार भी थाम दी है। सुबह-सुबह काम पर निकलने वाले लोग कोहरे के बीच रास्ता तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। कई स्थानों पर 15-20 मीटर आगे तक देख पाना भी मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर वाहन हेडलाइट जलाकर चलते दिखाई दे रहे हैं। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं भारी वाहनों की आवाजाही भी धीमी हो गई है। कोहरे के चलते सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहने से लोग अतिरिक्त सतर्कता बरतते दिख रहे हैं। कोहरे का असर रोजगार पर भी साफ नजर आ रहा है, हालांकि स्कूलों में अभी शीतकालीन अवकाश होने से बच्चों को बड़ी राहत मिली है।दफ्तरों और खदानों में काम करने वाले कई कर्मचारी तय समय से

देर से पहुंच रहे हैं। बसें और अन्य यात्री वाहन निर्धारित समय से देरी से पहुंच रहे हैं, जिससे यात्रियों को बस स्टैंड में परेशानी उठानी पड़ रही है।

मौसम में आए इस बदलाव के साथ ही ठंड ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह और शाम की ठिठुरन लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर कर दी है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों, बस स्टैंड और रिहायशी इलाकों में जगह-जगह अलाव जलते नजर आ रहे हैं। गर्म चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है, जो ठंड से राहत पाने का एक जरिया बन रही हैं। इस मौसम का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों पर देखा जा रहा है। ठंड के कारण सर्दी, खांसी और वायरल जैसी समस्याओं में इजाफा होने लगा है। चिकित्सकों का कहना है कि बदलते मौसम में खासतौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है और गर्म कपड़े पहनने के साथ-साथ खान-पान पर भी ध्यान देना चाहिए। दोपहर के समय जब सूर्य देव ने अपनी हल्की-सी झलक दिखाई दे रही है तो मानो पूरे क्षेत्रवासी राहत की सांस ले रहे हैं। धूप निकलते ही वातावरण में गर्माहट आने व कोहरे की परत धीरे-धीरे छंटने पर जनजीवन फिर से रफ्तार पकड़ता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में भी सुबह और रात के समय घना कोहरा और कड़ाके की ठंड बनी रह सकती है।सतर्कता और सावधानी ही इस मौसम में सुरक्षित रहने का सबसे बेहतर उपाय है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के सेंट्रल प्रभारी मनीष ने किया प्रतापपुर का दौरा

बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर पोषण आहार उपलब्ध कराने के निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। भारत सरकार, नीति आयोग द्वारा नामांकित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के एकमात्र आकांक्षी विकासखंड प्रतापपुर के सेंट्रल प्रभारी अधिकारी मनीष मुखर्जी ने सोमवार को प्रतापपुर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक में संचालित विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया तथा आमजन से संवाद कर ब्लॉक की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान श्री मुखर्जी ने कलेक्टर एस. जयवर्धन से मुलाकात कर आकांक्षी विकासखंड में संचालित विकास कार्यों एवं उनकी प्रगति को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बच्चों एवं महिलाओं के कल्याणकारी कार्यक्रम, पेयजल तथा बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं सहित क्षेत्र के समग्र विकास पर चर्चा की गई। भ्रमण के क्रम में सेंट्रल प्रभारी अधिकारी द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर सोनगरा, केरता शक्कर कारखाना एवं आंगनबाड़ी केंद्र गोटगवां का निरीक्षण किया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं शक्कर कारखाने में उत्पादन एवं रोजगार की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की स्थिति एवं महिलाओं को प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर पोषण आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आमजनो से भी संवाद कर ब्लॉक की प्रगति की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ 7 जनवरी 2023 को मुख्य सचिवों के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के दूरस्थ एवं कम विकसित ब्लॉकों में शासन व्यवस्था को सुदृढ़ कर नागरिकों के जीवन स्तर एवं सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके तहत मौजूदा योजनाओं के अभिसरण, परिणामों के निर्धारण तथा निरंतर निगरानी के माध्यम से विकास की कमियों को दूर किया जाता है। आकांक्षी ब्लॉक पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत 219 जिलों के लिए केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय एवं अभिसरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ जिलों को विकासात्मक हस्तक्षेपों के त्वरित क्रियान्वयन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके नियमित भ्रमण से प्रगति की समीक्षा, बाधाओं की पहचान एवं जिला प्रशासन को समय पर सहयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

कलेक्ट्रेट में 1 जनवरी से बायोमेट्रिक डिवाइस से अधिकारियों, कर्मचारियों का लगेगा अटेंडेंस

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 01 जनवरी 2026 से कलेक्टोरेट में आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली प्रारम्भ किया जाना है। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देश पर

आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली मे कलेक्ट्रेट परिसर में लगने वाले समस्त कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी का पंजीयन एनआईसी के सहयोग से किया जा रहा है। इसके साथ ही संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को उनके अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारीगण का रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट https:\\cggad.attendance.gov.in. में सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं । सभी का पंजीयन 01 जनवरी से पूर्व कराने के निर्देश दिए ताकि सभी आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का हिस्सा बन सके। इस संबंध में डिप्टी कलेक्टर श्री रमेश मोर ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर श्री एस.जयवर्धन के निर्देश के अनुपालन में जिला संयुक्त कार्यालय के अंतर्गत संचालित होने वाले सभी विभागीय कार्यालय के 175 अधिकारी एवं कर्मचारीगण का पंजीयन सुनिश्चित किया जा चुका है। इसके साथ ही आधार

सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से अधिकारी एवं कर्मचारी परिचित हो सके और इसके उपयोग करने की प्रक्रिया को समझ सके, इसके लिए ऑनबोर्ड हो चुके अधिकारी एवं कर्मचारियों को अभी से आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के उपयोग हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि ऑन बोर्ड हो चुके अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा स्वयं को अभ्यस्त करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल किया जाना सुनिश्चित किया जा चुका है। अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय आने के समय और जाने के समय बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अपनाने की दिशा में अपना कदम बढ़ा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ में बिछेगा मेट्रो का जाल, डिप्टी सीएम साव बोले- तेज गति से होगा काम

रायपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। छत्तीसगढ़ में मेट्रो का जाल बिछाने को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, मेट्रो का काम प्रारंभिक स्तर पर है। चीन, अमेरिका के बाद भारत मेट्रो का जाल बिछाने में तीसरे स्थान पर पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में तेज गति से आने वाले समय में काम होगा। वहीं दलहन-तिलहन लगाने खरीदी की अनुमति मिलने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि दलहन तिलहन को बढ़ावा देने एक ऐतिहासिक कदम है। दलहन-तिलहन लगाने का क्रम कम हुआ था, मगर अब किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही हाल ही में शामिल हुए नगरीय निकायों की बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि उत्तर मध्य क्षेत्रों के 5 नगरीय प्रशासन विभागों की बैठक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई। भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, पीएम आवास, स्वच्छता अभियान, मोबिलिटी के कामों की समीक्षा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 'सर्वे' को लेकर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सर्वे कौन रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। मगर किसी को डराने का विषय नहीं है। जो गड़बड़ नहीं किया है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। बिना तथ्यों के आधार पर बात नहीं करना चाहिए। आरोप-प्रत्यारोप से बचना चाहिए।

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरूद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

ग्रामीणों पर लाठी-डंडा बरसाकर कोल माइन्स का संचालन मंजूर नहीं

खदान बंद करने और एफआईआर खारिज करने की मांग पूरी नहीं हुई तो एनएच में चक्काजाम की चेतावनी

नवपदस्थ कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीण खदान बंद करके मनाएंगे गांव गणराज्य दिवस

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। एसईसीएल विश्रामपुर क्षेत्र द्वारा लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत स्थित अमेरा खुली खदान के लिये किए गए विस्तार को ग्राम पंचायत परसोड़ीकला के ग्रामीणों ने गैर कानूनी बताते हुए अवैध रूप से खुली खदान को बंद कराने और ग्राम सभा सदस्यों के विरूद्ध कराए गए एफआईआर को खारिज करने की मांग की है। सोमवार को काफी संख्या में कलेक्टोरेट कार्यालय अंबिकापुर पहुंचे महिला-पुरूषों ने कहा कि 24 दिसम्बर के पूर्व उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए ग्रामसभा को अवगत नहीं कराने पर सरगुजा संभाग के सभी पंचायतों की ग्रामसभाएं संयुक्त रूप से अंबिकापुर-बिलासपुर हाइवे में एक दिवसीय चक्काजाम करते हुए गांव गणराज्य दिवस मनाएंगे। गांव में रैली निकालकर एसईसीएल की अवैध खदान को बंद कराएंगे और गांव को स्वतंत्र कराने की पहल करके राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

पारम्परिक आदिवासी महासभा के संयोजक जंगसाय पोया, ग्राम सभा अध्यक्ष रामबाई मराबी सहित अन्य ने इस पर जोर देते हुए कहा कि ग्रामीणों पर लाठी, डंडा बरसाकर कोल माइन्स का संचालन किसी कीमत पर बर्दास्त नहीं किया जाएगा। कानून को ताक में रखकर और ग्रामीणों पर दबाव बनाकर जिस प्रकार ग्राम सभा की धज्जी उड़ाई जा रही है, नियमों के विपरीत भूमि अधिग्रहण कानून का माखौल उड़ाया जा रहा है, कोल बेयरिंग एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है, इसका जोर-शोर से विरोध किया जाएगा। परसोड़ीकला की सरपंच करिश्मा सिंह, अमृत राम, गोवर्धन राम, दिनेश राम सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि भारतीय संविधान पांचवीं अनुसूची के तहत सरगुजा जिला अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहां पेशा कानून 1996 एवं छ.ग. पेशा अधिनियम 2022 प्रभावी है। वन अधिकार अधिनियम 2006 व संशोधित अधिनियम 2012 की धारा 5 सामुदायिक वन अधिकार का प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही अधिग्रहण की प्रक्रिया गलत एवं कानून के विपरीत है। इसके बावजूद बीते 3 दिसम्बर, बुधवार को अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, थाना प्रभारी लखनपुर एवं एसईसीएल व एलसीसी के महाप्रबंधक संजय सिंह, राघवेन्द्र पाण्डेय के अगुवाई में बिना ग्राम सभा प्रस्ताव व सूचना के अमेरा खदान के विस्तार हेतु ग्रामवासियों पर डंडा बरसाया गया, जिसमें कई ग्रामीण घायल हो गए। अश्रु गैस के गोले बरसाए गए। बेहोश महिलाओं को घसीटते हुए ले गए, इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। आरोप है कि इस दौरान दो बकरा और एक बकरी को भी मारकर अपने साथ ले गए। कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया गया। सिंचाई के साधनों को तोड़-फोड़ दिया गया। घटना से सभी ग्रामीण डरे, सहमे हैं। इनका कहना है कि प्रशासनिक अमला एसईसीएल अमेरा के अधिकारियों के साथ मिलकर ग्रामीणों पर अत्याचार करने में लगा है।

ग्रामसभा के सम्मान से खिलवाड़

ग्रामीणों ने परसोड़ीकला में पूर्व में घटित हुई घटना की निष्पक्ष जांच कराते हुए गैरकानूनी तरीके से खोली गई खदान को तत्काल बंद कराने और 150 ग्राम सभा सदस्यों के ऊपर दर्ज कराए गए फर्जी एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मारपीट करने वाले व कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाने वालों, दोषी अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रशासन के अधिकारी ग्राम सभा के सम्मान और अधिकार को बरकरार रखें, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी ग्राम सभा के निर्णय का उल्लघंन करने की हिम्मत न करे।

ब्लू प्रिंट और शिक्षण शास्त्र पर व्याख्याताओं को मिला 5 दिवसीय प्रशिक्षण

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और आगामी बोर्ड परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को प्रावीण्य सूची में स्थान दिलाने के उद्देश्य से विकासखंड प्रतापपुर में 17 से 21 दिसम्बर तक आयोजित पांच दिवसीय 'ब्लूप्रिंट प्रश्न निर्माण एवं शिक्षण शास्त्र' प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शिविर में विज्ञान समूह के व्याख्याताओं को आधुनिक शैक्षणिक पद्धतियों और बोर्ड के सटीक परीक्षा पैटर्न से रूबरू कराया गया।

प्रशिक्षण के दौरान जिला स्तर से प्रशिक्षित अनुभवी मास्टर ट्रेनर्स ने विषयवार गहन सत्र लिए, जिसमें ब्लू प्रिंट के आधार पर अंकों के विभाजन और कठिन विषयों को सरल बनाने की तकनीकों पर चर्चा की गई। रसायन विज्ञान की विषय विशेषज्ञ श्रद्धा गुप्ता ने रसायन विज्ञान के जटिल समीकरणों, अभिक्रियाओं और ब्लू प्रिंट के अनुसार महत्वपूर्ण अध्यायों से प्रश्न तैयार करने की बारीकियां सिखाई। गणित के व्याख्याता रविन्द्र सोनी ने तार्किक क्षमता और गणितीय कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया। भौतिक शास्त्र के विशेषज्ञ एस.के. गुप्ता ने भौतिकी के सिद्धांतों और प्रयोगात्मक प्रश्नों के चयन पर मार्गदर्शन दिया। जीव विज्ञान के व्याख्याता देव रतन रवि ने जीव विज्ञान के चित्रों और वर्णनात्मक प्रश्नों को ब्लूप्रिंट के आधार पर संयोजित करना बताया।

शिक्षा नीति और सतत विकास पर मंथन

राज्यपाल पुरस्कृत व्याख्याता अजय कुमार चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सतत विकास के लक्ष्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रशिक्षण में ब्लूम टैक्सनॉमी, एनसीएफ भारतीय ज्ञान परंपरा, व्यसन मुक्ति और विद्यालय में सीखने हेतु उपयुक्त वातावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी सत्र आयोजित किए गए। प्रशिक्षण टीम में आर.बी. सिंह, मनीषा एक्का, संतोष भारती ने एनसीएफ, भारतीय ज्ञान परंपरा, व्यसन मुक्ति और विद्यालय में सीखने हेतु उपयुक्त वातावरण पर प्रशिक्षण दिया।

विद्यार्थियों का भविष्य शिक्षकों के हाथ में-संयुक्त संचालक

संयुक्त संचालक संजय गुप्ता ने निरीक्षण के क्रम में कहा विद्यार्थियों का भविष्य शिक्षकों के हाथ में है। उन्होंने व्याख्याताओं द्वारा तैयार किए गए ब्लू प्रिंट और अध्यापन कौशल का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए कहा कि शिक्षकों को इस तकनीक का उपयोग कक्षा 10वीं और 12वीं के उन बच्चों को चिन्हित करने में करना चाहिए, जिन्हें विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य केवल उत्तीर्ण होना नहीं, बल्कि श्रेष्ठ परिणाम लाना होना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों को प्रेरित करते हुए समाज और देश के विकास में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। उनके उत्साहजनक मार्गदर्शन से सभी व्याख्याता आत्मविश्वास से भर गए और बेहतर परिणाम लाने के लिए आश्वस्त किया।

बीईओ ने दिया ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन पर जोर

विकासखंड शिक्षा अधिकारी एम.एस. धुर्वे ने प्रशिक्षण के दौरान नियमित उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि इस पांच दिवसीय कार्यशाला की सार्थकता तभी है जब शिक्षक विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों के समक्ष इसका प्रयोग करें। उन्होंने परीक्षा परिणाम सुधारने हेतु तकनीकी निर्देशों के अक्षरशः पालन की अपील की।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उत्सव में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधिमंडल होंगे शामिल

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 24 दिसंबर को भारत मंडपम, नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उत्सव 2025 का आयोजन डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशलता पूर्वक त्वरित निपटान की थीम पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा नामित 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा लेंगे, जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग अंबिकापुर के सदस्य नवनी कान्त दत्ता भी शामिल हैं।

कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों से राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ से नामांकित प्रतिनिधिमंडल में राज्य उपभोक्ता आयोग रायपुर से श्रीनिवास तिवारी रजिस्ट्रार, प्रमोद वर्मा सदस्य, जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों में आनंद कुमार सिंघल बिलासपुर, छमेश्वर लाल पटेल रायगढ़, रंजना दत्ता कोरबा, डाकेश्वर प्रसाद शर्मा रायपुर तथा सदस्यों में अरविंद परिहार धमतरी, संध्या वाजपेयी दुर्ग, विशाल तिवारी जांजगीर-चांपा एवं नवनी कान्त दत्ता शामिल हैं।

जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा के सदस्य दत्ता ने बताया कि न्यायमूर्ति एवं अध्यक्ष, गौतम चौरड़िया छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से उपभोक्ता विवादों का डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशलता पूर्वक त्वरित निपटान हेतु तथा भविष्य में सभी उपभोक्ता आयोगों को पेपरलेस करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सरगुजा जिला सहित छत्तीसगढ़ राज्य के सभी उपभोक्ता आयोगों में ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन एवं ई-हियरिंग की सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसकी नियमित निगरानी भी राज्य आयोग द्वारा की जा रही है, जिससे दूरस्थ अंचल में निवासरत कोई भी पक्षकार घर बैठकर सुलभ और प्रभावी ढंग से अपनी शिकायत ऑनलाइन कर सके है और सुनवाई में हिस्सा भी ले सकें। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य पर नई दिल्ली में आयोजित उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं एवं उपलब्ध न्याय व्यवस्था के मध्य दूरी को कम करके न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुलभ, किफायती एवं प्रभावी बनाना है।

मजबूत मन मजबूत जीवन का आधार है-शिल्पा पाण्डेय

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। उदयपुर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में छात्राओं के बीच विजन समाजसेवी संस्था द्वारा मजबूत मन मजबूत जीवन विषय पर 'जीवन अनमोल है' थीम को लेकर जन जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार एवं समाजसेवी संतोष दास ने कहा कि छात्राओं का कठिन संघर्ष और अनुशासन देखकर सहज कहा जा सकता है कि वे मानसिक रूप से मजबूती की दिशा में हैं। कस्तूरबा उदयपुर में बच्चियों का समन्वय एवं एकाग्रता देखकर मन अत्यंत खुश है, मेरा आप सभी बच्चों को यही संदेश है कि कभी भी जीवन से मत हारिए, भले पढ़ाई में नंबर कम आ जाए पर जीवन का नंबर कम नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम की संयोजिका अधिवक्ता एवं समाज सेविका शिल्पा पाण्डेय ने कहा कि मजबूत मन मजबूत समाज का आधार होता है। कभी भी यदि मन निराश हो तो अपने माता-पिता के विषय में सोचना चाहिए। जो तकलीफ माता-पिता ने बच्चों की परवरिश करने में उठाई है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहे। सकारात्मक दिशा, सकारात्मक जीवन का पर्याय होता है। कार्यक्रम में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की अधीक्षिका सरोजिनी प्रमिला ने भी विजन समाजसेवी संस्था के इस अनूठे प्रयास की सराहना की और बच्चों की मानसिक मजबूती को बच्चों के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि हर स्थिति में हम छात्राओं के साथ हैं। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की बच्चियों ने लिखित में चिट्ठियां लिखकर ऐसी बातें समाज सेविका शिल्पा पांडे से शेयर की, जो वे किसी को नहीं बताना चाहती थीं, लेकिन यह उनके लिए मानसिक समस्या का कारण था। शिल्पा पांडे ने एक-एक करके ऐसी बच्चियों की काउंसलिंग की और उन्हें मजबूत जीवन जीने की प्रेरणा दी।

पति को लेकर दो महिलाएं भिड़ी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। पति को छीनने का आरोप लगाते हुए दो महिलाओं की आपस में भिड़ गईं। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र में स्थित नवापारा स्वास्थ्य केन्द्र के पास की है। पैरामैडिकल की छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसके पति पूर्व में एक युवती से विवाह किए थे, उसको छोड़ने के बाद वर्ष 2024 में उसके साथ प्रेम विवाह किए हैं। दोनों गांधीनगर में किराए का कमरा लेकर बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं। 20 दिसम्बर को दोपहर करीब 1.30 बजे के लगभग युवक की वर्तमान पत्नी प्रेग्नेंसी का टीका लगवाने के लिए नवापारा अस्पताल गई थी। अस्पताल के पास उसकी मुलाकात उसके पति की पूर्व पत्नी से हो गई, जो पति को छीन लेने का आरोप लगाते हुए सार्वजनिक स्थल पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गई। इस दौरान सहेली ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया। घटना से क्षुब्ध युवती ने गांधीनगर थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी है, जिस पर पुलिस ने आरोपिया के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।

सरस्वती महाविद्यालय में सात दिवसीय एनएसएस शिविर का ग्राम मोरभंज में समापन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरस्वती महाविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना का सात दिवसीय विशेष शिविर 16 दिसंबर को प्रारंभ हुआ था, जिसका समापन 22 दिसंबर को ग्राम मोरभंज में हुआ। इस शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में सेवा भावना, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूकता विकसित करना रहा। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नैन साय, संतोष मुखर्जी, कृष्ण चंद मुखर्जी, रामप्रकाश पंच (कर्मटिया) रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ऋषि सिंह ने की। शिविर का संचालन कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में हुआ। सात दिवसीय शिविर की थीम 'नशा जागरूकता' रही। शिविर के दौरान एनएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा नशा उन्मूलन को लेकर जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता अभियान, श्रमदान, पोस्टर प्रदर्शनी तथा ग्रामीणों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वयंसेवकों ने ग्रामीणों को नशे से होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया। समापन अवसर पर एनएसएस के स्वयंसेवक रामनिधि, सुषमा, पूजा, आशीष, अम्पेटदीप, शालिनी, मंदीप, सादाम, श्रेया, आंचला देवांगन सहित अन्य स्वयंसेवकों ने सात दिनों में किए गए कार्यों के अनुभव साझा किए। स्वयंसेवकों ने बताया शिविर से उनमें अनुशासन, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता एवं समाज सेवा की भावना का विकास हुआ। अतिथियों ने स्वयंसेवकों एवं ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में नशा मुक्ति को समाज की प्राथमिक आवश्यकता बताते हुए युवाओं से नशे से दूर रहकर सकारात्मक एवं स्वस्थ जीवन अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने स्वयंसेवकों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में परिवर्तन की दिशा तय करते हैं। कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने सात दिवसीय शिविर के दौरान संपन्न सभी गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया और स्वयंसेवकों के समर्पण की प्रशंसा की। प्राचार्य डॉ. ऋषि सिंह ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि यह शिविर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ नशा मुक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिविर के सफल आयोजन में सहायक प्राध्यापक प्रवीण शर्मा, मलय दास, कृष्ण त्रिपाठी, तोलेश्वर राजवाड़े, सूरज कुमार, रानू निशा, धनकुंवर पैकरा, आराधना त्रिपाठी एवं नरेंद्र बंजारे सहित अन्य प्राध्यापकों का सहयोग रहा। अंत में स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया और राष्ट्र सेवा की शपथ के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

पीजी मेडिकल सीटों में 75 प्रतिशत ओपन मेरिट अधिसूचना छत्तीसगढ़ के छात्रों के साथ अन्याय

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। प्रदेश युवा कांग्रेस आरटीआई विभाग हिमांशु जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा वर्ष 2025 की पीजी मेडिकल सीटों को लेकर जारी की गई 75 प्रतिशत ओपन मेरिट अधिसूचना प्रदेश के होनहार छात्रों और डॉक्टरों के भविष्य के साथ अन्याय है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि भाजपा सरकार को न तो छत्तीसगढ़ के युवाओं की चिंता है और न ही राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की। राज्य के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थियों ने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दी, आज उसी राज्य में उन्हें केवल 25 प्रतिशत पीजी सीटों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि 75 प्रतिशत सीटें बाहरी राज्यों के छात्रों के लिए खोल दी गई हैं। यह छत्तीसगढ़ के छात्रों के अधिकारों का सीधा हनन है। भाजपा सरकार का यह फैसला न केवल स्थानीय डॉक्टरों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार है, बल्कि इससे भविष्य में राज्य के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी होगी। जो छात्र यहीं पढ़े, यहीं सेवा दी, वही आज सबसे अधिक उपेक्षित हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार राज्य के युवाओं का होना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह छत्तीसगढ़ के युवाओं के हितों के विरुद्ध नीतियां बनाकर केवल राजनीतिक और प्रशासनिक तुष्टिकरण में लगी हुई है। युवा कांग्रेस, की ओर से मांग की गई है कि आउटसोर्सिंग को बढ़ावा न देते हुए 75 प्रतिशत ओपन मेरिट वाली अधिसूचना को तत्काल रद्द किया जाए। राज्य के स्थानीय छात्रों के लिए पर्याप्त आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। मेडिकल छात्रों और डॉक्टर संगठनों से संवाद कर न्यायसंगत नीति बनाई जाए। यदि भाजपा सरकार ने इस जनविरोधी निर्णय को वापस नहीं लेगी, तो युवा कांग्रेस आंदोलन, प्रदर्शन और लोकतांत्रिक संघर्ष के लिए बाध्य होगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा।

पशुधन के शीतलहर प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश जारी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शीत ऋतु को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से आवश्यक तैयारी एवं बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पशु चिकित्सा सेवाएं के उपसंचालक ने पशुधन के शीतलहर प्रबंधन हेतु जिले के समस्त वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ को पत्र जारी कर जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर के माध्यम से जन समुदाय में जमीनी स्तर पर प्रचार-प्रसार कर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है, जिसमें पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाईयां एवं चारा भण्डारण, ठंडी हवाओं से बचाव हेतु पशु आवासों को सभी दिशाओं से ढंकने, पशुधन के आहार एवं खानपान में वृद्धि करने, उच्च गुणवत्ता वाले चारा या चारागाहों का उपयोग करने, जलवायु अनुरूप शेड का निर्माण करने, जानवरों के बैठने हेतु सूखा भूसा रखने कहा गया है। उन्होंने पालतू जानवरों को शीत लहर से बचाने के लिए भवन के अंदर रखने तथा उन्हें कंबल से ढकने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करते हुए अपने-अपने संस्था अंतर्गत नजदीकी गौशाला, गौधाम व अन्य स्थल जहां पशुओं को रखा गया है का भ्रमण, भौतिक निरीक्षण करने कहा है।

संस्कारों में परिवर्तन लाकर परम आनंद और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराता है राजयोग

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा यूएनजीए द्वारा 21 दिसंबर को घोषित विश्व ध्यान दिवस, जिसका थीम विश्व एकता एवं विश्वास हेतु ध्यान अंतर्गत प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंबिकापुर द्वारा मेडिटेशन कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. विजय द्विवेदी, होली क्रॉस हॉस्पिटल की साइकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योति माला, आर्ट ऑफ लिविंग के संचालक अजय तिवारी, समाजसेवी वंदनादत्ता, अनिल मिश्रा, मंगल पांडे एवं ब्रह्माकुमारी संचालिका सरगुजा संभाग बीके विद्या द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी ने अपने विचार और अनुभव को साझा किया। ब्रह्माकुमारी विद्या ने बताया कि ध्यान मेडिटेशन एक अलौकिक विद्या है। योग विद्या के अभाव के कारण तनाव, डिप्रेशन, परेशानियां बढ़ रही हैं। निराकार परमपिता परमात्मा स्वयं ब्रह्मा तन का आधार लेकर राजयोग सिखा रहे हैं, यह एक प्राचीन योग है। राजयोग अर्थात आत्मा एवं परमात्मा का परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति की अनुभूति के आधार पर स्वयं को मन, बुद्धि की एकाग्रता द्वारा परमात्मा के साथ जोड़ती है, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान कर अपने व्यवहार, कर्म और संस्कारों में सकारात्मक और संतुलन का अनुभव कराता है। परमात्मा गुणों और शक्तियों के माध्यम से अपने संस्कारों में परिवर्तन लाकर परम आनंद और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराता है, तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाता है। अजय तिवारी ने बताया ध्यान अर्थात कुछ नहीं हूं, स्वयं को समझें तब ध्यान लगाया जा सकता है। यह नकारात्मक, व्यर्थ, दुख, अशांति इन सबसे हमें बाहर

निकालती है। समस्याओं का समाधान योग है। डॉ. ज्योतिमाला ने बताया राजयोग आज की जरूरत बन चुकी है, जिसके द्वारा हम अपने अंदर पॉजिटिविटी लातें हैं और अपने विचारों को देख पाते हैं। विजय द्विवेदी ने बताया कि ध्यान के द्वारा अपने अंदर की चीजों को देख पाते हैं। इस जनरेशन के लोगों को इस मार्ग में लाना चाहिए और इस दिशा में ब्रह्माकुमारी संस्था सही काम कर रही है। अनिल मिश्रा ने बताया मन का अनायास सोचना अर्थात हमें यह बताता है कि अब हमें ध्यान की और बढ़ना चाहिए इसलिए हमें अपने दिनचर्या में योग ध्यान मेडिटेशन को जरूर शामिल करना है। वरिष्ठ समाजसेवी मंगल पांडे ने बताया कि नवा बिहान टीम नशा मुक्ति जागरूकता अभियान ब्रह्माकुमारी संचालिका बीके विद्या के सहयोग से चलाया जा रहा है, जो देश, समाज में परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभा रहा है। वंदना दत्ता ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने तकलीफ और दुख से स्वयं को हल्का कर सकते हैं। बीके रेखा ने विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य पर गीत गाकर सबको भाव-विभोर कर दिया। बीके लल्लू ने अनुभव शेयर में बताया राजयोग मेडिटेशन द्वारा सकारात्मक विचारों से अपनी बीमारी को मैंने ठीक किया। बीके ममता ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया।

जनपद अध्यक्ष ने डी ग्रेड स्कूल का निरीक्षण किया

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। संकुल सखौली के डी ग्रेड स्कूल का निरीक्षण जनपद अध्यक्ष विक्रम सोनपाकर के द्वारा किया गया। उन्होंने भौतिक व शैक्षणिक अवलोकन कर के शिक्षा के गुणवत्ता सुधारने हेतु आवश्यक निर्देश दिया। इस अवसर पर संकुल प्रभारी प्राचार्य नेली अनीता कुजूर व संकुल समन्वयक मोहम्मद सलीम खान राही मौजूद रहे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर